For All Competitive Exams











Britannica troops from Afghanistan ...



News18
China Wants To Talk Peace Wit...



✓ Stars and Stripes
 US troops to leave Afghanistan by Sept ...



Newsinc24
US troops leave Afghanistan's airbase ...



Times of India
US troops in Afghanistan ...



The Hindu

Last troops exit Afghanistan, ending...



w Wikipedia 2020–2021 U.S. troop withdrawal from ...



WSJ Airport After U.S. Troops Leave Afghanistan



Maj. Gen. Chris Donahue: Who is the last American soldier to have left Afghanistan?

Donahue seen in image boarding last US military flight from Kabul



By Greg Norman · Fox News

August 31, 2021 8:08am EDT









•Former Pakistan ISI Chief

Taliban sweep into Kabul presidential palace, capping shock Afghanistan takeover

Spokesman says group will enter talks on forming 'inclusive Islamic government'; chaos grips capital as Westerners, Afghans attempt to flee

By AP 16 August 2021, 1:29 am











Taliban fighters take control of Afghan presidential palace after the Afghan President Ashraf Ghani fled the country, in Kabul, Afghanistan, Aug. 15, 2021. (AP/Zabi Karimi)



देश









शहर चुनें

होम

राज्य

शॉर्ट वीडियो

ओलंपिक 2024 किकेट

मनोरंजन

बिजनेस

करियर

विदेश

वेब स्ट



हार्दिक से दूर नताशा ने चीटिंग के पोस्ट लाइक करने के बाद लिखा-



देख डालिए ये टॉप 6 मर्डर मिस्ट्री फिल्में, क्लाइमैक्स ऐसा कि हिल जाएगा दिमाग



शाहरुख से इरफान तक ने TV से की करियर की शुरुआत, जानते हैं माधुरी के शो का नाम



जेल तोड़कर भागना इतना भी नहीं आसान, इन फिल्मों में दिखाई गई है अंदर की हकीकत



इस एक्टेस ने बताया था दिव्या भारती को पहले से था अपनी मौत का अंदेशा?

अफगानिस्तान में सरकार गठन में हो रही देरी के बीच ISI चीफ फैज हमीद पहुंचे काबुल, तालिबान के टॉप नेताओं से करेंगे बात

अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार में हो रही देरी के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। उनके साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद...



Aditya Kumar • हिन्दुस्तान, नई दिल्ली















■ Top stories :

TH The Hindu

Pakistan's former ISI chief Faiz Hameed taken into military custody: Army



The Economic Times

Pakistan: Former ISI chief Faiz Hameed taken into military custody, court-...



1 day ago



हाउसिंग घोटाले केस में ISI के पूर्व चीफ अरेस्ट: पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ, आर्मी ने...



1 day ago

№ NDTV

Video | Pakistan's Former
ISI Chief Faiz Hameed
Taken Into Army Custody

✓



1 day ago

VIDEO 1 day ago

More news \rightarrow



Al Jazeera

https://www.aljazeera.com > news > pakistans-ex-isi-chi...

Pakistan's ex-ISI chief faces court martial after arrest in ...

5 hours ago — No **former** spy **chief** has faced court martial in a country the powerful **army** has directly ruled for nearly three decades.









CBI



NIA



Inter-Services Intelligence

Government agency :



The Inter-Services Intelligence is the largest and best-known component of the Pakistani intelligence community. It is responsible for gathering, processing, and analyzing any information from around the world that is deemed relevant to Pakistan's national security. Wikipedia

इंटर सर्विस इंटेलीजेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलीजेंस सेवा है। 1950 में पूरे पाकिस्तान की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जिम्मा आईएसआई को सौंप दिया गया। इसमें सेना के तीनों अंगों के अधिकारी मिलकर आईएसआई के लिए काम करते हैं। पूर्व में इसका मुख्यालय रावलिपंडी में था और इसे "इंटेलीजेंस ब्यूरों" के नाम से जाना जाता था। विकिपीडिया



Indian, Pakistani Intel on High Alert Amid ISIS Threat 📀

14 hours ago — Islamic State, also known as **ISIS***, has evolved into a significant global threat since its emergence in the early 2010s. Its influence has ...



NDTV

https://www.ndtv.com > World News

ISIS-Linked Outfit Threatens Attack On India-Pak T20 World ...

30 May 2024 — **ISIS-**K has called for a "Lone Wolf" attack on the India-Pakistan World Cup Cricket match here next month, a top police official has warned.



South Asia Terrorism Portal

https://www.satp.org > islamist-extremism > data > Major...

Major Islamist Terrorist Attacks in India by Pakistan-Based ...

Command HQ- Muzaffarabad, **Pakistan** occupied Kashmir (PoK). ISI, Al Qaeda. October 18, 2001. Failed assassination attempt on Public Works Minister Ali Mohammad ...



पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हाउसिंग घोटाले केस में आर्मी ने 12 अगस्त को अरेस्ट कर लिया। फैज के खिलाफ यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई।

<mark>आर्मी ने उनका कोर्ट मार्शल शुरु कर दिया है</mark>। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली हुआ है कि ISI का पूर्व चीफ को किसी मामले में अरेस्ट किया गया है।

पिछले साल 14 नवंबर को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि फैज हमीद पर लगे आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये आरोप बेहद गंभीर है। कोर्ट ने कहा था कि अगर फैज दोषी साबित होते हैं, तो इससे देश की संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा।

A court-martial is a military court that tries members of the armed forces for offenses against military law. The court is made up of commissioned officers and sometimes enlisted personnel. The convening officer, such as a general, flag officer, or commander of a major military installation, chooses the officers who will sit on the court. The court determines the guilt or innocence of the defendant and, if found guilty, decides on a punishment.

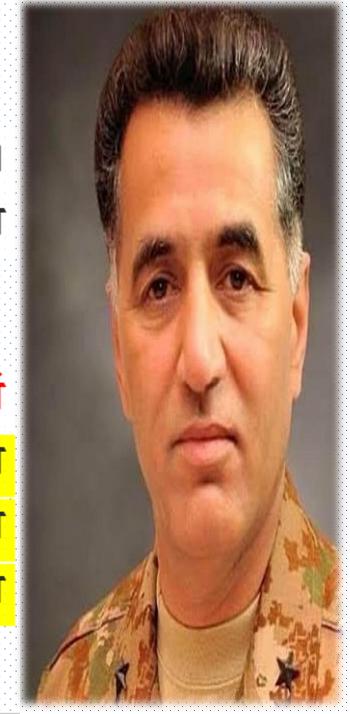
There are different types of courts-martial, including:
 General court-martial: Can try any offense and impose any penalty.

- Special court-martial: Can only impose short-term confinement and
- dishonorable discharge.
 Summary court-martial: Can try anyone subject to the Uniform Code of
- Military Justice (UCMJ) for noncapital offenses, except for officers, cadets, aviation cadets, and midshipmen. Summary courts-martial can't impose more than one month's confinement.

कौन है फैज हमीद

फैज हमीद पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्होंने साल 2019 से लेकर 2021 तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी काम किया है।

फैज का जन्म पाकिस्तान के चकवाल के लतीफाल गांव में हुआ था। हमीद ने 1987 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी को ज्वॉइन किया था। उन्होंने क्योटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी आर्मी की बलूच रेजीमेंट में कमीशन किया गया था।



जून 2019 से नवम्बर 2021 तक आईएसआई के मुखिया थे

जनरल हमीद वही शख्स हैं, जिसकी तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे की योजना में भी अहम भूमिका थी। इतना ही नहीं काबुल में तालिबान के दाखिल होने और अशरफ गनी के देश छोड़ने के साथ ही एक तस्वीर जो खूब चर्चाओं में आई थी, वो काबुल के एक होटल में चाय की चुस्कियां लेते जनरल हमीद की थी। जनरल हमीद जून 2019 से नवम्बर 2021 तक पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया थे। वहीं, सेना से रिटायरमेंट के पहले जनरल हमीद 31 कोर के कमांडर के रूप में तैनात थे।









Taliban sweep into Kabul presidential palace, capping shock Afghanistan takeover

Spokesman says group will enter talks on forming 'inclusive Islamic government'; chaos grips capital as Westerners, Afghans attempt to flee

By AP 16 August 2021, 1:29 am











Taliban fighters take control of Afghan presidential palace after the Afghan President Ashraf Ghani fled the country, in Kabul, Afghanistan, Aug. 15, 2021. (AP/Zabi Karimi)



देश









शहर चुनें

होम

राज्य

शॉर्ट वीडियो

ओलंपिक 2024 किकेट



मनोरंजन

बिजनेस

करियर

विदेश

वेब स्ट



हार्दिक से दूर नताशा ने चीटिंग के पोस्ट लाइक करने के बाद लिखा-



देख डालिए ये टॉप 6 मर्डर मिस्ट्री फिल्में, क्लाइमैक्स ऐसा कि हिल जाएगा दिमाग



शाहरुख से इरफान तक ने TV से की करियर की शुरुआत, जानते हैं माधुरी के शो का नाम



जेल तोड़कर भागना इतना भी नहीं आसान, इन फिल्मों में दिखाई गई है अंदर की हकीकत



इस एक्टेस ने बताया था दिव्या भारती को पहले से था अपनी मौत का अंदेशा?

अफगानिस्तान में सरकार गठन में हो रही देरी के बीच ISI चीफ फैज हमीद पहुंचे काबुल, तालिबान के टॉप नेताओं से करेंगे बात

अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार में हो रही देरी के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। उनके साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद...



Aditya Kumar • हिन्दुस्तान, नई दिल्ली









अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार में हो रही देरी के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे। उनके साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान भी साथ हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमीद तालिबान की टॉप लीडरशिप से मिलने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हामिद तालिबान शूरा के बुलावे पर काबुल गए हैं।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के साथ इस बैठक में पाकिस्तान और तालिबान की सुरक्षा, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। काबुल पहुंचने पर फैज हमीद ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि हामिद सरकार गठन में हो रही देरी और तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान सिहित कई मसलों पर तालिबान से बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से हमीद काबुल पहुंचने वाले प्रमुख विदेशी अधिकारी हैं और इससे यह भी साबित होता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच कैसे रिश्ते हैं।



Home DETPrime Markets Market Data News Industry Rise Politics Wealth MF Tech Careers Opinion NRI Panache ETTV Spotlight

India Decoded Web Stories Morning Brief Podcast Newsblogs Economy - Industry ET Explains Politics More -

Business News + News + Defence + Imran Khan-Gen Qamar Javed Bajwa fight over ISI chief refuses to die down

Imran Khan-Gen Qamar Javed Bajwa fight over ISI chief refuses to die down

By Dipanjan Roy Chaudhury, ET Bureau . Last Updated: Oct 14, 2021, 08:55:00 AM IST



Synopsis

Khan on Tuesday told his cabinet he had told Chief of the Army Staff (COAS) Gen Qamar Javed Bajwa he wanted Lt Gen Hameed to continue as ISI director general for some time due to the critical situation in neighbouring Afghanistan, ET has reliably gathered.



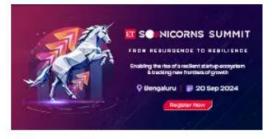
The Khan-Bajwa meeting was also confirmed by Pakistan Information Minister Fawad Chaudhry during his presser after Tuesday's cabinet meeting.

The controversy over appointment of new ISI chief is refusing to die down with Pakistan PM Imran Khan insisting on continuing with Lt Gen Faiz Hameed who has been transferred out by the army chief as Corps Commander of Peshawar.

Khan on Tuesday told his cabinet he had told Chief of the Army Staff (COAS) Gen Qamar Javed Bajwa he wanted Lt

Gen Hameed to continue as ISI director general for some time due to the critical situation in neighbouring Afghanistan, ET has reliably gathered.







साल 2023 में टॉप सिटी हाउसिंग के मैनेजमेंट ने फैज हमीद पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने इसके मालिक मोइज खान के ऑफिस और घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद नवंबर 2023 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को अपनी शिकायत रक्षा मंत्रायल में दर्ज कराने के लिए कहा था।

इन आरोपों की जांच के लिए सेना ने अप्रैल में एक जांच कमेटी का गठन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इस समिति का गठन जवाबदेही तय करने के लिए किया गया था। इस कमेटी की को एक मेजर जनरल लीड कर रहे थे।

पिछले साल मार्च में तत्कालीन गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि <mark>फैज हमीद और उनके भाई के</mark> खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही है।

फैज हमीद पाकिस्तान की सेना में पेशावर के कोर कमांडर भी रहे हैं। उन पर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी सेना के नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगा है। फैज हमीद पर ISI चीफ के तौर पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। पूर्व ISI चीफ फैज हमीद ने अल कादिर ट्रस्ट स्कैम केस में 5 अरब रुपए की रिश्वत ली थी। यह खुलासा इमरान सरकार में मंत्री रहे और उनके दोस्त फैजल वाबडा ने किया था।

अल कादिर ट्रस्ट स्कैम वही केस है, जिसमें पिछले साल 9 मई को इमरान को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त हिंसा हुई थी। 8 लोग मारे गए थे। आर्मी हेडक्वॉर्टर के अलावा जिन्ना हाउस पर भी खान समर्थकों ने हमला किया था।

इस हमले के बाद सेना और सरकार ने एक्शन लिया था। इसका असर ये हुआ था कि इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 80 से ज्यादा बड़े नेता, सांसद और विधायक पार्टी छोड़ गए थे।



क्या है अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें इमरान खान की हुई गिरफ्तारी, पत्नी बुशरा भी हैं आरोपी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया है. इमरान को अल-कादिर ट्रस्ट केस के सिलसिले में अरेस्ट किया है. इस मामले में इमरान की बीवी बुशरा खान भी आरोपी हैं. इमरान आज दोपहर में दो मामलों की सुनवाई में शामिल होने के लिए कोर्ट पहुंच रहे थे. खान को पाक रेंजर्स ने कोर्ट परिसर से हिरासत में ले लिया.





इमरान खान पर अल-कादिर ट्रस्ट मामले में धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज हैं. ये पूरा विवाद अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और उनके करीबी सहयोगी जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान ने अल-कादिर प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया था, जिसका उद्देश्य पंजाब के झेलम जिले की सोहावा तहसील में 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' प्रदान करने के लिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना करना था. आरोप है कि <mark>दान की गई जमीन के दस्तावेज में हेरफेर किया</mark> गया. यूनिवर्सिटी के लिए इमरान और उनकी बीवी ने जमीन को गैर कानूनी तरीके से

को गिरफ्तारी के नाम पर धमकाकर अरबों रुपये की जमीन अपने नाम करा ली.

हड़प लिया और दोनों ने पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स मलिक रियाज





तालिबान से भारी पड़ी यारी: ISI चीफ फैज हमीद की छुट्टी, इमरान के चहेते थे; US और आर्मी चीफ बाजवा बिफरे हुए थे

इस्लामाबाद 3 वर्ष पहले









चाय की प्याली में तूफान का असर



आर्मी चीफ की मंजूरी के बगैर काबुल गए थे फैज

सेरेना होटल में तालिबान नेताओं के साथ चाय पी

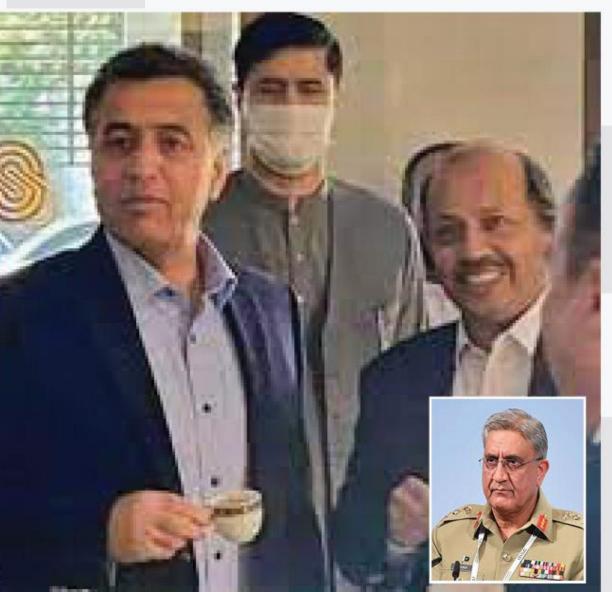
बाजवा ISI चीफ की इस हरकत पर सख्त खफा

अमेरिका ने पाक को नतीजे भुगतने की धमकी दी

अफगानिस्तान में तालिबान की जबरिया हुकूमत बनवाने में मदद करने वाले पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज हमीद को पद से हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI चीफ फैज पिछले महीने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मंजूरी लिए बगैर काबुल गए थे। वहां तालिबान नेताओं के साथ सेरेना होटल में टी-पार्टी अटैंड की थी। आरोप है कि उन्होंने वहां तालिबान की हुकूमत कायम करने में मदद की थी।

जनरल फैज इमरान खान की पसंद थे और अगले साल आर्मी चीफ बनने वाले थे। बताया जाता है कि उनकी काबुल यात्रा से जनरल बाजवा के अलावा अमेरिका भी काफी नाराज था। जनरल नदीम अंजुम ISI के नए चीफ होंगे।

चाय की प्याली में तूफान का असर



आर्मी चीफ की मंजूरी के बगैर काबुल गए थे फैज

सेरेना होटल में तालिबान नेताओं के साथ चाय पी

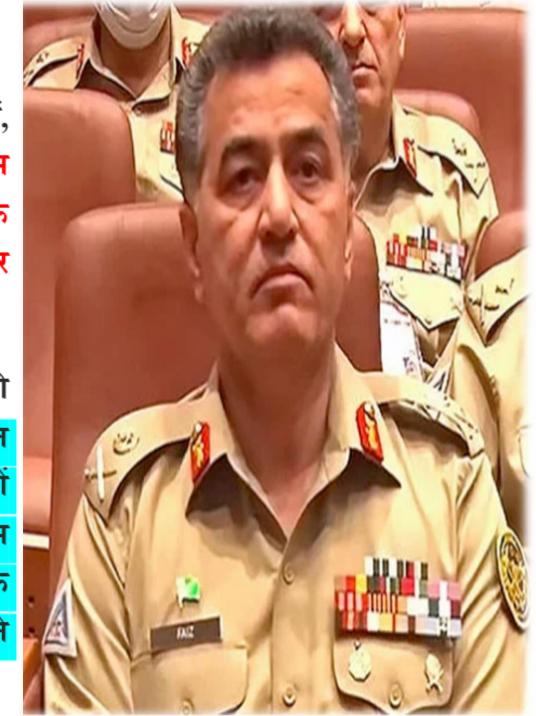
बाजवा ISI चीफ की इस हरकत पर सख्त खफा

अमेरिका ने पाक को नतीजे भुगतने की धमकी दी

तनातनी की खबरें लंबे वक्त से थीं

जनरल हमीद को हटाए जाने की खबरें लंबे वक्त से चल रही थीं, लेकिन आर्मी की दबदबे के चलते पाकिस्तान का मेन मीडिया इन खबरों को दबा रहा था। हमीद को पेशावर कॉर्प्स कमांडर का चीफ बनाकर भेजा गया है। आर्मी चीफ ने टॉप लेवल पर कुछ और फेरबदल भी किए हैं।

ये भी सही है कि जनरल हमीद और बाजवा के बीच तनातनी की खबरें काफी पहले से चल रही हैं। माना जा रहा है कि तीन साल पहले रावलिपंडी में आर्मी के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर दोनों के बीच मतभेद शुरू हुए थे। बाद में जब इमरान ने बाजवा को तीन साल का एक्सटेंशन दिया तो यह रस्साकशी खुलकर मुल्क के सामने आ गई। फैज कई बार बाजवा को भरोसे में लिए बगैर फैसले करने लगे थे।



तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल के साथ ही करीब-करीब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। दुनिया को पहले ही शक था कि पाकिस्तान फौज और ISI तालिबान की पूरी मदद कर रही है। सितंबर की शुरुआत में जनरल फैज हमीद चुपचाप काबुल पहुंचे। यहां एक ही फाइव स्टार होटल है। इसका नाम सेरेना होटल है।

यहां वे तालिबान के आला नेताओं के साथ हाथ में चाय का प्याला लेकर कहकहे लगा रहे थे। संयोग से इसी होटल में ब्रिटेन की एक महिला जर्निलस्ट मौजूद थी। उसने न सिर्फ फैज के फोटो लिए, बल्कि कुछ सवाल भी किए। इसके जवाब में फैज ने सिर्फ इतना कहा- ऑल इज वेल। बस यहीं से यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजवा और अमेरिका हमीद पर बिफर गए। इमरान पर उन्हें हटाने का दबाव बढ़ता चला गया।

Pakistan's ex-ISI chief faces court martial after arrest in property case

No former spy chief has faced court martial in a country the powerful army has directly ruled for nearly three decades.







UPPSC,RO/ARP,BPSC,UP TEST SERIES

TEST SERIES)

35+ MOCK TESTS

- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

UPP

TEST SERIES)

- 20+ MOCK TESTS
- 8+ PYQ'S
- 25+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

Download | Application **Apni Pathshala**

7878158882

🕟 Apni.Pathshala 🧧 Avasthiankit

🕇 AnkitAvasthiSir 💟 kaankit

ANKIT AVASTHI SIR







A

GA FOUNDATION



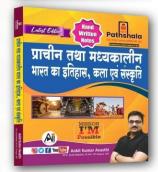


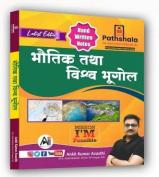


6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट













अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

- → सिन्धु नदी का उद्यम क्षेताका प्रवितिय क्षेत्र में बीखर पू → तिल्बत में इस निर्ण को सिंगी खंबान कहते हैं।
- → यह पमचीक नामक स्थान की भारत में प्रवेश करती है। - घट नदी भारत में लहान तथा जास्कर श्रीनी के बीच
- वहती है।
- -) पाकिस्तान में यह सरक (Attock) नामक स्थानों पर मैवानों में प्रवेश करती है।
- → पाकिस्तान में कराँची के पास डेस्टा बनाते हुए धर अस्व सागर में जिस्ती है।
- → सिंह्य नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक निदेवों :-रयोज , तुषा , दुनजा , गिलागीट , स्वात , काबुल तथा गीगल
- -) इसकी अनुय बायें हाथ की सहायक निदयां क्षेतम , चिनाव रावी , व्यास , सत्तवं , ट्रांस तथा जारकर
- → सिंधु भी पंचनद भान में निठानकीट नामक स्थान पर मिलती 🖺
- → 'लैंह' मिंधुं नदी के किनारें स्थित है।

4444

ं दीलम :- इस नवी का उत्गम जम्मू कवमीर में



Title:

Date: __/__/_

वैरिनाग झील से होता है।

- * यह नदी वूलर सील का निर्माण करती है भी भारत की सबसे बड़ी मीढ़े पानी की सील है।
- -) इस निक के किनार भीनगर स्थित है।
- -) किश्वानगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी हैं।
- ्र इस नदी पर तुलकुल परियोजना प्रस्तावित है। थए एक नीवहन परियोजना दे।
- → यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तरिहरीय सीमा का निमिं करती है।
- ii) चिनाब : चिनाब नदी का उपगम हिमाचल प्रदेश में वारालन्द्या दर्वे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
- 🛶 उ ६ ८ में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन प्रीयोजनाएँ स्थित है।

उदाहरण :- दुलहस्ती , सतान , बगितहार

- 🛶 यह सिंधु नदी की सबसे वडी शद्ययं नदी 🗞।
- iii) <u>रावी</u>: = वावी नदी का उद्गम शैहताँग दर्रे के पास भी हिमान्यल उदेश में हीता है।
- → हिमायस प्रवेश में इन नदी पर प्रमेश बाँद्य स्थित है।
- → पंजाब में इस नदी पर धीन परियीजना स्थित E।







Rahul yadav

CAL CENTRE

787815882







AnkitInspiresIndia

















Godi Media In India



























MEDIA

'Unworthy of a Democracy': India Ranks 159 of 176 Countries on Press Freedom Index



The Wire Staff 03/May/2024 • 5 min read











"With violence against journalists, highly concentrated media ownership, and political alignment, press freedom is in crisis in "the world's largest democracy"," RSF noted.













The New York Times







Anti Hindu Anti India media/channels

2024 लोकसभा चुनाव को लेकर

रविश कुमार ने किया बड़ा खुलासा







Enable Inline Keywor

अपने बनाये हथियार से हारी BJP!! लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का प्रभाव...by Ankit...

1.1M views · Streamed 2 months ago 1.4x

Ankit Inspires India 4.14M subscribers



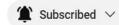
अपने बनाये हथियार से हारी BJP !! लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का प्रभाव...by Ankit Avasthi Sir



Ankit Ins... ②















E

ELECTION 2024

INDIA ELECTION RESULTS

BJP

240

CONGRESS

99

OTHERS

204











अब OTT और online current affairs को रेगुलेट करेगी सरकार !! जानिए क्या है मामला ? by Ankit Sir



507.567 views Streamed live on 27 Nov 2023 #AnkitSir #AnkitInspiresIndia #ankitavasthisir



Ministry of Information and Broadcasting Proposes Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023

The draft Bill provides for a consolidated framework to regulate the broadcasting services in the country and seeks to replace the existing Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and other Policy Guidelines currently governing the broadcasting sector in the country

Read the proposed bill here: mib.gov.in/sites/default/...





Ministry of Information and Broadcasting proposes **Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023**



Consolidated Legal Framework for Broadcasting sector



Content Evaluation Committees for adherence to Programme & Advertisement Code



Broadcast Advisory Council to replace Inter-Departmental Committee



Accessibility measures for persons with disabilities

Send feedback and comments on the Bill to:



sb-moib@gov.in







Subscribe

Home

HT Premium

Games & Puzzles



Vinesh Phogat Verdict Live

NIRF Ranking 2024 Live

Hin

MIB withdraws draft of Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2024

By Aditi Agrawal

Aug 12, 2024 06:18 PM IST





The draft was circulated for feedback as part of an ongoing process of consultations that began in November 2023 when the ministry uploaded the first draft.



2024 Election & Power Of People

The MIB on Monday has withdrawn the latest draft of the Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2024 by asking all stakeholders to return physical copies given to them between July 24 and 25.

The stakeholders were told that their comments are no longer required.

#BroadcastingBill #RahulGandhi #KanganaRanaut #Hindenberg



MIB withdraws draft of Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2024

By Aditi Agrawal



As news reports come in on the withdrawal of the Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2024, I would like to thank everyone who reported, worked and educated others on its dangerous provisions. This is a broad coalition of diverse individuals, groups and organisations who have stood up and asked the government for transparency and contested political censorship.

My own assessment is that these reports indicate merely a retreat and an official ministerial statement or admission in parliament is necessary for confirmation. However, small victories do matter and it's important to pause and cheer for public accountability.

Hope that the MIB practices the Pre-Legislative Consultation Process (PLCP) in letter and spirit for future legal proposals. I hope to continue providing a political economy framing and a detailed legal analysis that advances policy and public deliberation.

7:43 PM · Aug 12, 2024 · **141.4K** Views



@apar1984

काल करे सो आज कर। Advocate practising in Delhi. Co-founder & former ED (2018-24) @internetfreedom. Fellow @Ashoka. Geek out on the law, tech and democracy.

1,333 Following 47.2K Followers

देश के मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। मंत्रालय बिल का नया मसौदा तैयार करेगा। साथ ही सभी साझेदारों (स्टेकहोल्डर्स) से 24-25 जुलाई 2024 के बीच दी गईं ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी वापस करने को कहा है।

सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा- हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (रेगुलेशन) बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को साझेदारों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। हमें सभी साझेदारों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए थे।





Ministry of Information and Broadcasting Proposes Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023

The draft Bill provides for a consolidated framework to regulate the broadcasting services in the country and seeks to replace the existing Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and other Policy Guidelines currently governing the broadcasting sector in the country

Read the proposed bill here: mib.gov.in/sites/default/...





Ministry of Information and Broadcasting proposes **Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023**



Consolidated Legal Framework for Broadcasting sector



Content Evaluation Committees for adherence to Programme & Advertisement Code



Broadcast Advisory Council to replace Inter-Departmental Committee



Accessibility measures for persons with disabilities

Send feedback and comments on the Bill to:

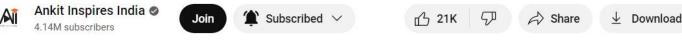


sb-moib@gov.in





अब OTT और online current affairs को रेगुलेट करेगी सरकार !! जानिए क्या है मामला ? by Ankit Sir



507,567 views Streamed live on 27 Nov 2023 #AnkitSir #AnkitInspiresIndia #ankitavasthisir

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर 2023 को <mark>ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (रेगुलेशन) बिल 2023</mark> पेश किया जिसका उद्देश्य ब्राडकास्टिंग क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए एक नया नियामक ढांचा <mark>बनाना था .</mark> इस ड्राफ्ट के संबंध में मंत्रालय ने लोगों से <mark>फीडबैक</mark> मांगा . ट्विटर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा कि माननीय प्रधान मंत्री के 'व्यवसाय और जीवनयापन करने में आसानी' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, हमें प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक का ड्राफ्ट पेश करने पर गर्व है. उन्होंने लिखा कि ये महत्वपूर्ण कानून हमारे प्रसारण क्षेत्र के नियामक ढांचे को आधुनिक बनाता है. साथ ही पुराने रूल्स, गाइडलाइन आदि को रिप्लेस कर भविष्य-केंद्रित दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करता है. यानि इस बिल में नए टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया गया .

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा ने कि ये बिल ओटीटी के बदलते स्वभाव, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, आईपीटीवी और अन्य की गतिशील दुनिया को अपनाता है और तकनीकी एडवांसमेंट और इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है. ध्यान दें, फिलहाल ये एक एक ड्राफ्ट है जो पहले लोकसभा में पास होगा और फिर राज्यसभा में रखा जाएगा. दोनों सदनों से पास होने के बाद नए नियम लागू होंगे.



Advancing the Honorable Prime Minister's vision for 'Ease of Doing Business' and 'Ease of Living,' we're proud to introduce the draft Broadcasting Services (Regulation) Bill.

This pivotal legislation modernizes our broadcasting sector's regulatory framework, replacing outdated Acts, Rules, and Guidelines with a unified, future-focused approach.

It adapts to the dynamic world of OTT, Digital Media, DTH, IPTV, and more, promoting technological advancement and service evolution.

Key innovations include the establishment of 'Content Evaluation Committees' for robust self-regulation and the transformation of the Inter-Departmental Committee into a broader 'Broadcast Advisory Council,' fostering inclusive decision-making.

In line with our commitment to inclusivity, the bill specifically caters to the Divyangjan community with comprehensive accessibility guidelines.

Your feedback is invaluable. I invite all stakeholders to contribute their insights and help shape this landmark bill, a significant step towards a more efficient, inclusive, and forward-thinking broadcasting ecosystem.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI

10th November, 2023

PUBLIC NOTICE

ON WEBSITE OF MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

SOLICITING SUGGESTIONS/FEEDBACKS/COMMENTS/INPUTS/VIEWS FROM GENERAL PUBLIC/STAKEHOLDERS ON THE DRAFT "BROADCASTING SERVICES (REGULATION) BILL, 2023"

General public/stakeholder is hereby informed that the MIB has prepared a draft "Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023" to cater to the evolving needs of the Broadcasting Sector. Once enacted, this bill shall replace the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. The draft Bill is attached to this notice as **Annexure-I**. To facilitate better comprehension of the aforementioned draft bill, an explanatory note has been provided at **Annexure II**.

Any person/stakeholder desirous of sending views/comments/suggestions on the proposed legislation may do so by 09.12.2023 in the prescribed proforma at **Annexure-III** through email at jsb-moib@gov.in.

(Subhash Kumar)

Deputy Secretary

ब्राडकास्टिंग सर्विसेस को नए तरीके से रेगुलेट करेगा बिल

नया प्रसारण सेवाएँ (विनियमन) विधेयक 2023 देश में प्रसारण सेवाओं को रेगुलेट करने के लिए एक एकीकृत ढांचे का प्रावधान करता है और मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और वर्तमान में देश में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अन्य नीति दिशानिर्देशों को बदलने का प्रयास करता है.

इस बिल में 6 चैप्टर, 48 खंड और तीन अनुसूचियां शामिल हैं. इसकी प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हुए, मंत्रालय के एक विरष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये बिल न केवल ओटीटी सामग्री, डिजिटल समाचार और वर्तमान मामलों को शामिल करने के लिए नियामक दायरे का विस्तार करता है बल्कि भविष्य में विकसित किसी भी नए प्लेटफॉर्म को शामिल करने का विकल्प भी खुला रखता है.

कंटेंट रेगुलेशन के लिए बनेगी समिति

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कहा कि ये बिल सेल्फ कंटेंट रेगुलेशन के लिए मुल्यांकन समितियों और इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी को ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी कॉउंसिल में बदलता है ताकि फास्ट डिसीजन लिए जा सके. साथ ही ये बिल व्यक्तियों की विशिष्ट विकलांग आवश्यकताओं को भी संबोधित करता है.



प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- मसौदा विधेयक में ऑपरेटरों और प्रसारकों के लिए सलाह, चेतावनी, निंदा या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड का प्रावधान किया गया है। श्रृंखलाबद्ध अपराधों के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
- विधेयक में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने और प्लेटफार्म सेवाओं के वहन के प्रावधान भी शामिल हैं।
- प्रसारण क्षेत्र, खास तौर पर केबल टीवी के डिजिटलीकरण के साथ, विनियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत बढ़ रही है। इसमें कारोबार को आसान बनाना और प्रसारकों और वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन बढ़ाना शामिल है।
- यह 'विषय-वस्तु मूल्यांकन समितियों' की शुरूआत के साथ स्व-नियमन को बढ़ाता है और मौजूदा अंतर-विभागीय समिति को अधिक सहभागी और व्यापक 'प्रसारण सलाहकार परिषद' में विकसित करता है।
- यह विधेयक व्यापक सुगम्यता दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करके विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करता है।





Games & Puzzles

Crickii

Loan ₹10 Lakh

NIRF Ranking 2024 Live Kolkata Doctor Case Live India Post GDS Merit 2024 Live

Feedback on broadcasting bill to be taken in a few months: Anurag Thakur

By Aditi Agrawal X, New Delhi

Jan 25, 2024 07:42 AM IST







The ministry of information and broadcasting will work on getting feedback on the Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023 in the next few months, around the time India goes to polls, I&B minister Anurag Thakur said on Wednesday.



Union minister Anurag Thakur. (PTI)

The ministry of information and broadcasting will work on getting feedback on the Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023 in the next few months, around the time India goes to polls, I&B minister Anurag Thakur said on Wednesday.





Ashwini Vaishnaw informs #RajyaSabha that #Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023, was still in the #drafting stage in a written response to a question raised by #TMC MP Jawhar Sircar

Reports @Aditi_muses | #MIB #BroadcastingBill



From hindustantimes.com

11:22 AM · Jul 27, 2024 · 2,328 Views

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION No. 562

(TO BE ANSWERED ON 26-07-2024)

PROPOSED BROADCASTING LAW

562. SHRI JAWHAR SIRCAR

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) the main concerns raised by the Editors Guild of India, the National Alliance of Journalists, Delhi Union of Journalists and several others regarding the proposed Broadcasting Bill;
- (b) the Government's response thereto; and
- (c) the Government's plan to avoid overlap of jurisdiction in view of Acts and Rules Amendments under the IT Act on data, private communications and public expressions on TV, films, OTT, YouTube platforms, social media as well as digital journalism?

ANSWER

THE MINISTER OF RAILWAYS, INFORMATION AND BROADCASTING, AND ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

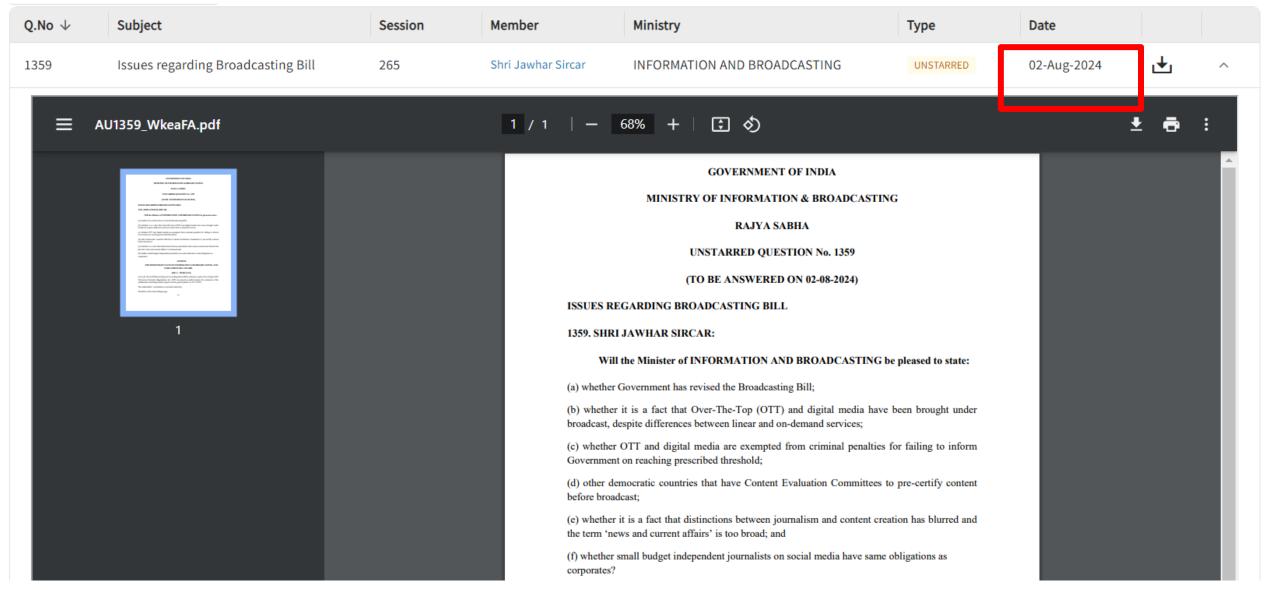
(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a), (b) & (c): The draft Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023 was placed in public domain for feedback and comments of the stakeholders, including domain experts and general public.

The Bill is still at the drafting stage.

Login





ANSWER

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(DR. L. MURUGAN)

(a) to (f): The draft Broadcasting Services (Regulation) Bill, seeking to replace the existing Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 was placed in public domain for comments of the stakeholders including domain experts and the general public on 10.11.2023.

The stakeholders' consultation is currently underway.

The Bill is still at the drafting stage.



🔊 Jawhar Sircar 🥏 @jawharsircar · Aug 2

Modi Govt suppresses truth from Parliament

— but shares information with business houses and 'stakeholders'. Govt HAS revised Broadcasting Bill & HAS CIRCULATED SECRETLY — yet it refuses to say this.

It avoids rest of ques — as no democratic country has such a draconian law.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION No. 1359

(TO BE ANSWERED ON 02-08-2024)

ISSUES REGARDING BROADCASTING BILL

1359. SHRI JAWHAR SIRCAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether Government has revised the Broadcasting Bill;
- (b) whether it is a fact that Over-The-Top (OTT) and digital media have been brought under broadcast, despite differences between linear and on-demand services;
- (c) whether OTT and digital media are exempted from criminal penalties for failing to inform Government on reaching prescribed threshold;
- (d) other democratic countries that have Content Evaluation Committees to pre-certify content before broadcast;
- (e) whether it is a fact that distinctions between journalism and content creation has blurred and the term 'news and current affairs' is too broad; and
- (f) whether small budget independent journalists on social media have same obligations as corporates?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(DR. L. MURUGAN)

(a) to (f): The draft Broadcasting Services (Regulation) Bill, seeking to replace the existing Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 was placed in public domain for comments of the stakeholders including domain experts and the general public on 10.11.2023.

The stakeholders' consultation is currently underway.

The Bill is still at the drafting stage.

....

Jawhar Sircar 🔮

@jawharsircar

Rajya Sabha MP of Trinamool Congress. Was in IAS & Govt, 42 yrs, Secretary, Gol & CEO of Prasar Bharati (DD, AIR). Upholds India's values - Plurality, Democracy

61 Following 59.1K Followers



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND **BROADCASTING**



Broadcast bill for YouTubers, indie journalists 'restrictive'

The first draft of The Broadcast Services (Regulation) Bill, 2024, was published for public consultation last November. The revised version was revealed to limited stakeholders recently and is yet to be shared with the public.



Barkha Kumari

Last Updated: 07 August 2024, 03:31 IST

Follow Us:









The latest draft of the Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2024 introduces significant changes to the regulation of broadcasting in India, expanding its scope to include OTT content, digital news, social media accounts, and online video creators.

The Bill seeks to replace the 1995 Cable Television Networks (Regulation) Act and now requires prior registration with the government for various digital news broadcasters, sets standards for content evaluation, and aims to validate the "Code of Ethics" prescribed under the Information Technology Rules, 2021.



The Ministry of Information and Broadcasting has proposed introducing onerous regulations on independent news creators on social media platforms like YouTube, Instagram and X. Union Minister Ashwini Vaishnaw in Parliament on August 7 (PTI Photo)

In a draft law, shared with a handful of industry stakeholders in a watermarked format to prevent leaking of the copy to a wider audience, the Ministry of Information and Broadcasting has proposed introducing onerous regulations on independent creators of news events on platforms like YouTube, Instagram and X – sparking concerns over freedom of speech and expression and the government's powers to regulate it.



The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995





8:16 PM · Aug 2, 2024

The Broadcasting Services (Regulation) Bill is a direct threat to our freedom of speech and independent media. Here's why we all must raise our voice against the government's tyranny:

- Increased government control over content creators, from social media influencers to independent news outlets, threatens the independence of the press and restricts free speech.
- The bill labels anyone uploading videos, making podcasts, or writing about current affairs as 'digital news broadcasters.' This could unnecessarily regulate individuals and small teams providing independent news coverage.
- Requiring online creators to establish content evaluation committees adds pre-publication censorship. This will delay timely news and create a chilling effect on free expression.

- The bill imposes heavy regulatory burdens on small content creators, treating them like large media corporations. Many independent journalists lack resources to comply, leading to potential shutdowns.
- Content creators who monetize their platforms face the same stringent regulations as traditional broadcasters. This discourages new entrants and harms the economic viability of independent creators, this is exactly how the government finished the crypto market in India.
- The drafting process of the bill did not include civil society, journalists, and key stakeholders, raising concerns about transparency and inclusivity.
- Monitoring 'negative influencers' and criminal liability for noncompliance threatens dissenting voices and independent journalism.

This bill will pave the way for excessive surveillance in the online world.



How does the government want to regulate independent news creators online? In the 2023 version of the draft, the Bill defined news and current affairs

programmes as: "(i)newly-received or noteworthy audio, visual or audiovisual programmes or live programmes, including analysis, about recent events primarily of socio-political, economic or cultural nature, or (ii) any programmes transmitted or retransmitted on broadcasting network, where the context, purpose, import and meaning of such programmes implies so."

However, in the 2024 draft has a new category called "digital news broadcaster" or "publisher of news and current affairs content" has been created, and defined as "any person who broadcasts news and current affairs programme through an online paper, news portal, website, social media intermediary, or other similar medium as part of a systematic business, professional, or commercial activity but excluding replica e-papers."

INFLUENCERS MAY BE CLASSIFIED AS DIGITAL NEWS BROADCASTER

As per the draft bill, Instagram influencers and Youtubers, whose user base will be defined by the government, might be classified as "digital news broadcasters", according to a report in The Hindustan Times. Creators on TikTok may also be included, even though the app is banned in India.



It has been reported that these digital news broadcasters will be separate from OTT broadcasting services and registered digital media. The first draft of the bill had already proposed that OTT platforms, which have the freedom to create any kind of content, will be bound by a programme code.

The content creators reportedly will be required to notify the government of their presence within a month of the enactment of the legislation. This provision is also likely to apply to any account sharing news irrespective of follower count.

Reports said they may also have to register under a three-tier regulatory framework similar to OTT services such as Amazon Prime Video and Netflix.

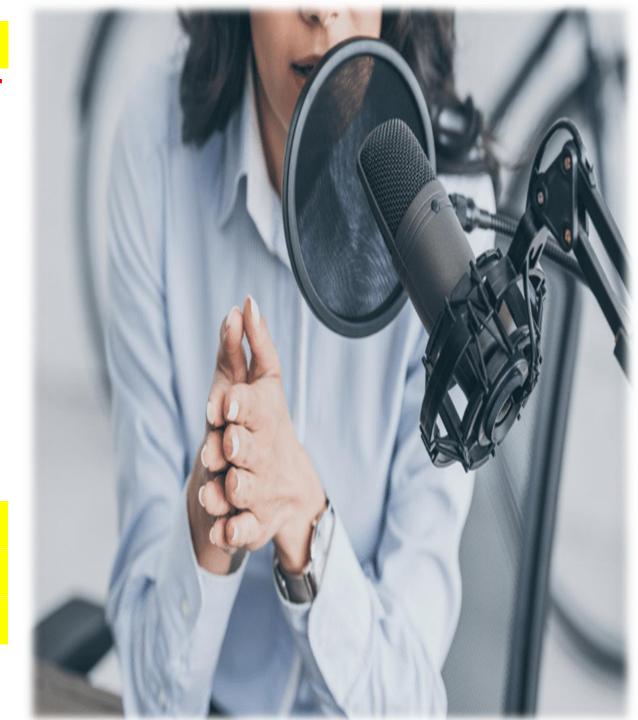
Moreover, they will also have to create a "content evaluation committee" at their own cost to screen the content before going live, the draft bill reportedly says. Those failing to do so will likely face criminal liability.

A significant aspect includes the establishment of a Broadcast Advisory Council, which will include five officers nominated by the Centre and professionals in the industry, to impose monetary penalties in case of violations.



Those who post news and current affairs on social media "as part of a systemic business, professional, commercial activity" will also be under its ambit, the report says. Thus, a podcast that has news commentary or a news blog that has Google AdSense enabled will have to adhere to the rules.

Another aspect of the proposed bill is that the regulations are likely to be applicable to all Internet users worldwide.



CRIMINAL LIABILITY FOR SOCIAL MEDIA FIRMS LIKELY

Social media companies such as Meta, YouTube and X, which are classified as intermediaries, are likely to attract criminal liability if any information sought from them by the government is not provided.

Also, the draft bill makes the user, rather than the social media intermediary, responsible for ensuring compliance with the rules.

Moreover, advertising networks like Google Adsense, Facebook Audience Network, and Taboola are also likely to be brought under the legislation's ambit and be classified as "advertising intermediaries".

It reportedly defines them as "an intermediary which primarily enables the buying and selling of advertising space on the internet or placement of an advertisement on online platforms without itself endorsing the advertisement".

ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल, 2024 के प्रावधान

इसे डिजिटल या OTT प्लेटफॉर्म जैसे- Youtube, X (Twitter), Facebook, Instagram, Netflix, Prime Video पर पब्लिश किए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट किया गया है।

- बिल आने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज पब्लिश करने वाले ब्रॉडकास्टर्स को 'डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर' के तौर पर जाना जाएगा।
- डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए नई रेगुलेटरी बॉडी 'ब्रॉडकास्टिंग ऑथिरिटी ऑफ इंडिया' (BAI) बनाए जाने का प्रावधान है।
- ब्रॉडकास्टिंग ऑथिरिटी ऑफ इंडिया नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े बिल केइंप्लीमेंटेशन और रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होगी।

- बिल में सेल्फ रेगुलेशन के लिए टू-टियर सिस्टम क्रिएट करने का प्रावधान है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन किमटी बनाने का प्रावधान है।
- कंटेंट इवैल्यूएशन किमटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होने वाले कंटेंट को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगी।
- र्डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट प्रोवाइडर्स और व्यूअर्स के बीच एक पारदर्शी और ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम तैयार करने का प्रावधान है।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स की बिल पर आपत्ति

- 90 से ज्यादा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डिजी-पब न्यूज इंडिया फाउंडेशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चुनिंदा साझेदारों के साथ बंद कमरे में इस पर चर्चा की। डिजिटल मीडिया संगठनों और सिविल सोसाइटी एसोसिएशन के साथ चर्चा भी नहीं हुई। ड्राफ्ट कॉपी पाने के लिए मंत्रालय को लेटर भी लिखा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
- बिल पर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स ने आपित्त जताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्राफ्ट में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को उनके यूजरबेस के आधार पर 'डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स' में दर्शाया जा रहा था। इसका नतीजा ये होता कि इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को अपने कंटेंट के लिए सरकार से रिजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता।
- इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स और डिजिटल पब्लिशर्स का कहना था कि बिल के जिए सरकार डिजिटल उन पर एक तरह से सेंसरशिप लगा रही है। बिल लागू होने पर सरकार की आलोचना नहीं की सकेगी।
- वहीं, टू-टियर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम पर भी साझेदारों का विरोध किया था। बिल के ड्राफ्ट में डेटा के लोकलाइजेशन और यूजर डेटा का एक्सेस सरकार के पास होने का एक प्रावधान जोड़ा गया था। इसे लेकर स्टेकहोल्डर्स का कहना था कि यह प्रावधान निजता का उल्लंघन करेगा। इसका दुरुपयोग की भी संभावना जताई थी।



DIGIPUB News India Foundation

@DigipubIndia

DIGIPUB has written to @MIB_India and @AshwiniVaishnaw requesting a conversation about the Broadcast Regulation Bill. We hope to hear from them and have a meaningful engagement.



DIGIPUB News India Foundation
 @DigipubIndia

...

Official Twitter handle of DIGIPUB News India Foundation | Membership open for digital-only ventures, freelance journalists and commentators.

38 Following 6,819 Followers

Dhanya Rajendran Chairperson



To, Shri Ashwini Vaishnaw, Minister of Information and Broadcasting Shastri Bhawan New Delhi-110001

29 July 2024

Subject: Follow-Up: Request for Meeting with the Ministry of Information and Broadcasting

Dear Shri Ashwini Vaishnaw.

I hope this email finds you well.

We are following up on our letter dated 19 June 2024, requesting a meeting with your office to discuss the concerns and suggestions of DIGIPUB News India Foundation regarding the digital news ecosystem.

We have also learned that a copy of the Broadcast Regulation Bill has been circulated to some news media organisations and media associations. DIGIPUB represents over 90 digital news media entities, commentators, and journalists across India, and our diverse coalition can provide valuable perspectives on the bill at hand.

We kindly request a copy of the bill and a convenient time for the meeting. We look forward to engaging in meaningful discussions to foster a healthy and robust news ecosystem in India.

Sincerely,

Dhanya Rajendran Chairperson alingat

Abhinandan Sekhri General Secretary

H

Ritu Kapur General Secretary

DIGIPUB News India Foundation executive@digipubindia.in

Press conference on the Broadcast Services Bill 2024



Press Release

DIGIPUB News India Foundation is holding a press conference to discuss the challenges and implications of the Broadcasting Services (Regulation) Bill 2024 for digital news media organisations, social media influencers, and online content creators.

The new provisions of the Broadcast Bill have far-reaching consequences for press and creative freedom, the operational viability of digital content creators, and the broader implications for India's digital ecosystem.

DIGIPUB, with 100 members, is the largest and the most diverse coalition of digital news media entities, media commentators, and journalists.

Ritu Kapur, co-founder and managing director of Quint Digital Media Limited and the general secretary of DIGIPUB; Ravish Kumar, former NDTV India editor and a Ramon Magsaysay awardee; Anant Nath, editor, The Caravan and president of the Editors Guild of India, Apar Gupta, advocate and co-founder of the Internet Freedom Foundation, will address the press conference on Thursday, 8 August 2024, at 6:00 pm in the Conference Room, Press Club of India, New Delhi.

Event: Press Conference

Date: 8 August 2024

Time: 6:00 pm

Venue: Press Club of India, 1, Raisina Road Near Central Secretariat Metro, Windsor Place, New Delhi, Delhi 110001



Press Release

DIGIPUB News India Foundation is holding a press conference to discuss the challenges and implications of the Broadcasting Services (Regulation) Bill 2024 for digital news media organisations, social media influencers, and online content creators.

The new provisions of the Broadcast Bill have far-reaching consequences for press and creative freedom, the operational viability of digital content creators, and the broader implications for India's digital ecosystem.

DIGIPUB, with 100 members, is the largest and the most diverse coalition of digital news media entities, media commentators, and journalists.

Ritu Kapur, co-founder and managing director of Quint Digital Media Limited and the general secretary of DIGIPUB; Ravish Kumar, former NDTV India editor and a Ramon Magsaysay awardee; Anant Nath, editor, The Caravan and president of the Editors Guild of India, Apar Gupta, advocate and co-founder of the Internet Freedom Foundation, will address the press conference on Thursday, 8 August 2024, at 6:00 pm in the Conference Room, Press Club of India, New Delhi.

Event: Press Conference

Date: 8 August 2024

Time: 6:00 pm

Venue: Press Club of India, 1, Raisina Road Near Central Secretariat Metro, Windsor Place, New Delhi, Delhi 110001



DIGIPUB

Non-profit organization :



digipubindia.in



The DIGIPUB News India Foundation is an Indian non-profit organization formed by digital media organizations. Wikipedia

☆ Translated by Google



DIGIPUB न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन डिजिटल मीडिया संगठनों द्वारा गठित एक भारतीय गैर-लाभकारी संगठन है। विकिपीडिया

Membership: Digital news media organizations;

"Independent journalists"; Commentators

Founded: 27 October 2020



DIGIPUB News India Foundation

Who We are

The DIGIPUB News India Foundation has been formed by digital media organisations with the intent to help ensure the creation of a healthy and robust news ecosystem for the digital age. The aim is to build a platform that represents digital news media organisations, with its membership open to **digital-only** ventures, as well as media commentators and independent journalists active in the digital news space.

Despite the growth of digital-only news organisations in India, there is no single body representing the country's digital news ecosystem. DIGIPUB News India Foundation aims to represent, amplify and evolve best practices that are independent and upholds the highest standards of journalism. The digital news ecosystem includes current issues, analysis, commentaries in any form: text, videos, animations, graphic stories, etc.

One of the aims of the Foundation is to underline the fact that the pursuits and interests of legacy media may not always be the same as that of digital media – especially in regards to regulation, business models, technology and structures. DIGIPUB News India Foundation has been created to address the need for an organization to represent the interests of digital-only news media.

One of the key defining aspects of the Foundation is that it does not believe that only organisations should represent or voice the needs of the digital news ecosystem. It is imperative to recognize the contribution of independent journalists informing the bulwark of this digital ecosystem. Membership to the DIGIPUB News India Foundation is also open to independent/freelance journalists and commentators who work in the digital news space.

The Foundation hopes to take the best practices from legacy media and hone these to specifically meet the needs of digital media. DIGIPUB News India Foundation looks forward to the support and collaboration of journalists, entrepreneurs, news professionals and news consumers, to nurture an organisation which will represent, define and protect this digital-only news ecosystem

The Values of DIGIPUB News India Foundation in Digital Journalism

We as digital news organisations, stand for the Constitutional values that are enshrined in the Indian Constitution in its Preamble



Justice, Social, Economic and Political



Liberty of Thought, Expression, Belief, Faith and Worship



Equality of Status and of opportunity irrespective of Caste, Class or Gender;



Promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the Nation

As news orga

Founding Members of DIGIPUB News India Foundation Organisations:

- Alt News
- Article 14
- Boomlive
- Cobrapost
- HW News
- Newsclick
- Newslaundry
- Scroll
- The News Minute
- The Quint
- The Wire

As news organisations, we seek to uphold the objectivity, fairness, integrity of our journalism, and being sensitive to the issues and the people involved in the news stories including their right to privacy. We oppose all attempts by organisations to reduce the media space by promoting fake news and using digital platforms for trolling, spreading hatred between communities and the people.







Press Conference | Broadcasting Services (Regulation) Bill 2024 | DIGIPUB News India Foundation



DIGIPUB News India Foundation
165 subscribers

Subscribe

45



⇔ Share

•••

Why is the Scope of the Draft Broadcasting Services (Regulation) Bill 2024 Significantly Expanded?

- Instances of sensational news during the 2024 Lok Sabha polls:
 - Independent content creators made videos on current affairs which made some sensational claims about the government and its senior leaders.
 - Hence, the need was felt to create **a system of accountability** for these creators, and to provide **a level-playing field** between mainstream press and independent creators.
- Content amplification by big-tech companies:
 - Another concern was the decisions made by tech companies' algorithms, and whether they ended up amplifying a certain narrative over another.
 - However, these companies have told the government that their algorithms serve users content depending on their browsing history.

SECRET

What legal obligations will independent creators have?

Now, if a creator is categorised as a digital news broadcaster, they must 'intimate' the MIB about their work and existence. They will also have to form one or more content evaluation committees at their own expense – and "strive to make" the committee diverse by including individuals with a knowledge of different social groups, women, child welfare, scheduled castes, scheduled tribes, minorities. The names of people in their CEC will also have to be shared with the government.

All digital news broadcasters must intimate the MIB. The 2023 version said that the government may prescribe a subscriber/viewer threshold that triggers intimation and content code obligations, but the latest version does not have this provision.



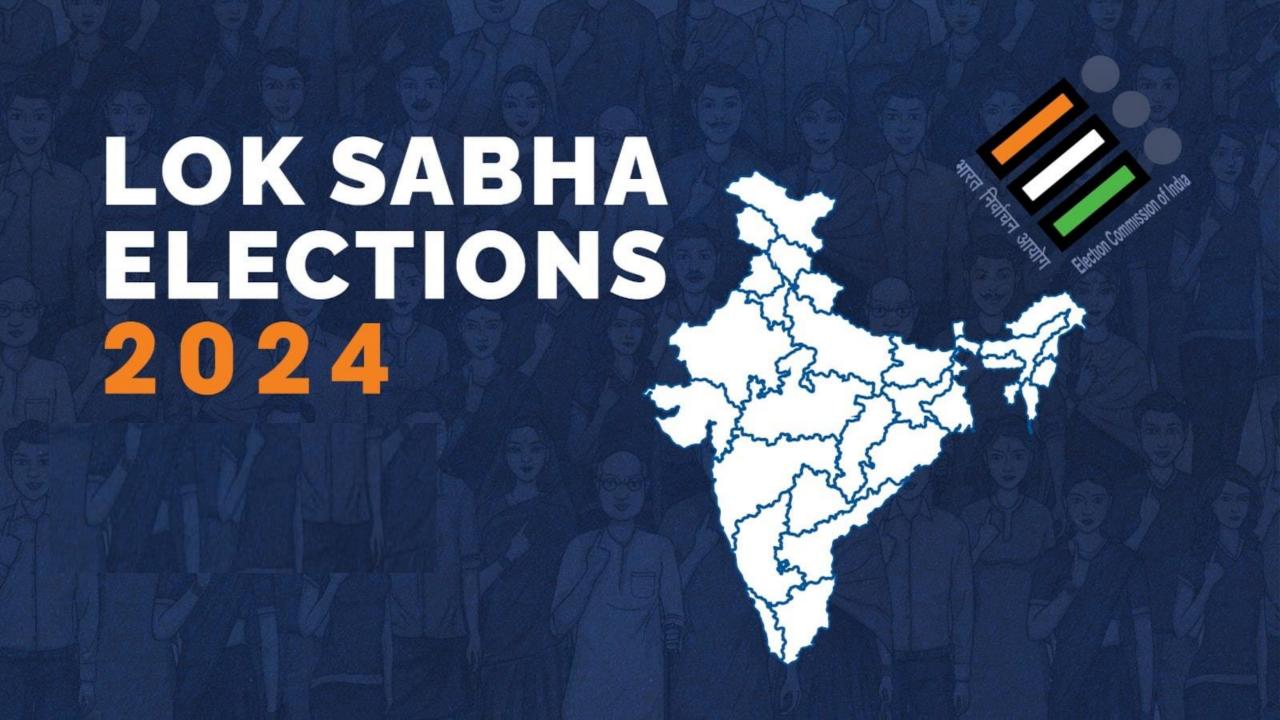
The penalty to not appoint such a committee is hefty under the current draft – news creators who do not intimate the Central Government names, credentials and other details of members of their CEC will be fined Rs 50 lakh in the first contravention, and Rs 2.5 crore for subsequent violations in the next three years. The draft Bill allows the government to "exempt a distinct class of players or a group for avoiding genuine hardship", which suggests that some stakeholders might be exempted from the purview of the Bill.

A senior government official explained that as the rules stand today, online content creators will have to issue an intimation to the government within a month about their operation and if they have appointed a content evaluation committee (CEC) – which they have to set up at their own cost. "As per our thought process right now, there will be a simple application which such broadcasters have to fill and send to the government," a second government official said.



Why does the government want to regulate independent news creators?

- It is understood that some of the big Indian creators of current affairs and news content on YouTube are on the government's radar. To be sure, as per the current wording under the Bill, even foreign creators may fall under its ambit, although enforcing Indian content regulations on them could be challenging.
- A senior government official said one key reason behind the significant expansion of scope in the current draft Bill compared to the version which was released for public consultation in November 2023 has been the "role a number of independent content creators played in the run-up to the 2024 Lok Sabha polls".
- "There were a number of instances where creators made videos on current affairs which made some sensational claims about the government and its senior leaders in the run up to the elections. That's when it was decided that there has to be an accountability measure for these creators as well, to create a level-playing field between mainstream press and independent creators," the official said.



What will social media companies need to do under the Bill?

The draft says that online intermediaries like Facebook, YouTube, and X are exempted from liability for third-party content, if:

- the function of the intermediary is limited to providing access to a communication system over which information made available by third parties is transmitted or temporarily stored or hosted;
- . the intermediary does not initiate the transmission;
- . the intermediary does not select or modify the information, except in compliance with government orders;
- . the intermediary observes due diligence while discharging his duties under this Act and observes other prescribed guidelines.

The Bill also has criminal liability provisions for social media companies if they do not provide information "pertaining to OTT Broadcasters and Digital News Broadcasters" on its platforms for compliance.

How does the proposed law compare to other countries?

In Singapore, both traditional broadcasters, and over the top (OTT) content providers fall under the country's broadcasting law. Under the country's copyright law, OTT platforms are regulated and they require a licence from a regulator, although licensees do not have the same level of obligations as other television services.

In the United States, the Federal Communications Commission (FCC) and its Media Bureau regulate broadcast radio and television stations. Currently, OTT platforms are not directly regulated by United States federal laws or government authorities.

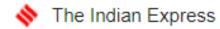


ARTICLE 19

"Everyone has the right to freedom
of opinion and expression;
this right includes
freedom to hold opinions without interference
and to seek, receive and impart information
and ideas through any media
and regardless of frontiers."

- Article 19; Universal Declaration of Human Rights

■ Top stories :



Why the withdrawal of the draft Broadcast Bill raises more questions than it answers

13 hours ago



The Indian Express

Facing criticism, Govt withdraws new draft of broadcast Bill



1 day ago

Moneycontrol

Govt withdraws controversial version of Broadcasting Bill 2024, to release fresh draft post October



1 day ago

देश के मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। मंत्रालय बिल का नया मसौदा तैयार करेगा। साथ ही सभी साझेदारों (स्टेकहोल्डर्स) से 24-25 जुलाई 2024 के बीच दी गईं ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी वापस करने को कहा है।

सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा- हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (रेगुलेशन) बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को साझेदारों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। हमें सभी साझेदारों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए थे।

मिनिस्ट्री ने कहा कि <mark>अब सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय</mark> दिया जा रहा है। और ज्यादा विचार-विमर्श के बाद बिल का एक नया ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। मंत्रालय विधेयक के ड्राफ्ट पर साझेदारों के साथ सिलसिलेवार विचार-विमर्श कर रहा है।



The Ministry of Information & Broadcasting is working on a Draft Broadcasting Services (Regulation) Bill.

The draft Bill was placed in public domain on 10.11.2023 along with the explanatory notes for comments of the stakeholders and the general public.

mib.gov.in/broadcasting/s...

In response, multiple recommendations/ comments/ suggestions were received including from various Associations.

Ministry is holding a series of consultations with the stakeholders on the draft bill.

Further additional time is being provided to solicit comments/ suggestions till 15th October, 2024.

A fresh draft will be published after detailed consultations.

9:36 PM · Aug 12, 2024 · 176.9K Views

1ST DRAFT CAME IN NOV

Ministry is holding a series of consultations with stakeholders on draft bill. Additional time is being provided to solicit comments till Oct 15, 2024. Fresh draft will be published after detailed consultations

-I&B ministry on X

- > A draft was first placed for comments **last Nov**
- ➤ Bill aims to overhaul rules
 governing broadcasting
 services. Has raised concerns
 over treating independent
 news creators as broadcasters



ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट जब से पब्लिक डोमेन में आया, तभी से विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर थीं और अघोषित तौर पर सेंसरशिप लाने का आरोप मढ़ रही थीं. विपक्ष ने संसद सत्र में भी इस मामले को उठाया और बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पत्रकारों से लेकर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और दूसरे स्टेक-होल्डर्स को कमेटी में शामिल करने की मांग की थी.

के लिए सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता. जिसे वो फ्री स्पीच पर हमला बता रहे थे.

ड्राफ्ट में एक प्रावधान था डाटा के लोकलाइजेशन और डाटा एक्सेस का. डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स और

कंटेंट क्रिएटर्स का तर्क था कि इससे डाटा का एक्सेस सरकार को मिल जाएगा और निजता का उल्लंघन

होगा. डाटा के दुरुपयोग की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. एक और महत्वपूर्ण बात यह थी

कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम इनफ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को उनके यूजर बेस या सब्सक्राइबर के

आधार पर डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में रखा गया था. इसका मतलब यह है कि उन्हें भी कंटेंट

विपक्ष का क्या तर्क, क्या मांग कर रहे थे

किस प्रावधान पर सबसे ज्यादा नाराजगी?





UPPSC,RO/ARP,BPSC,UP TEST SERIES

TEST SERIES)

35+ MOCK TESTS

- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

TEST SERIES)

- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

• 50+ MOCK TESTS • 30+ PYQ'S

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

UPP

TEST SERIES)

- 20+ MOCK TESTS
- 8+ PYQ'S
- 25+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

Download | Application **Apni Pathshala**

7878158882

🕟 Apni.Pathshala 🧧 Avasthiankit

🕇 AnkitAvasthiSir 💟 kaankit

ANKIT AVASTHI SIR









GA FOUNDATION



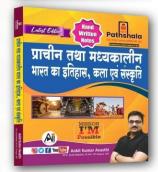


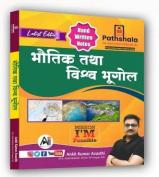


6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट













अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Date: _/_/_

Title:

→ सिन्धु नदी का उद्यम क्षेताका प्रवितिय क्षेत्र में बीखर पू

- → तिल्बत में इस निर्ण को सिंगी खंबान कहते हैं।
- → यह पमचीक नामक स्थान की भारत में प्रवेश करती है। - घट नदी भारत में लहान तथा जास्कर श्रीनी के बीच
- वहती है।
- -) पाकिस्तान में यह सरक (Attock) नामक स्थानों पर मैवानों में प्रवेश करती है।
- → पाकिस्तान में कराँची के पास डेस्टा बनाते हुए धर अस्व सागर में जिस्ती है।
- → सिंह्य नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक निदेवों :-रयोज , तुषा , दुनजा , गिलागीट , स्वात , काबुल तथा गीगल
- -) इसकी अनुय बायें हाथ की सहायक निदयां क्षेतम , चिनाव रावी , व्यास , सत्तवं , ट्रांस तथा जारकर
- → सिंघु भी पंचनद भान में निठानकीट नामक स्थान पर मिलती 🖺
- → 'लैंह' मिंधुं नदी के किनारें स्थित है।

4444

ं दीलम :- इस नवी का उत्गम जम्मू कवमीर में



Title:

Date: __/__/_

वैरिनाग झील से होता है।

- * यह नदी वूलर सील का निर्माण करती है भी भारत की सबसे बड़ी मीढ़े पानी की सील है।
- -) इस निक के किनार भीनगर स्थित है।
- -) किश्वानगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी हैं।
- ्र इस नदी पर तुलकुल परियोजना प्रस्तावित है। थए एक नीवहन परियोजना दे।
- → यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तरिहरीय सीमा का निमिं करती है।
- ii) चिनाब : चिनाब नदी का उपगम हिमाचल प्रदेश में वारालन्द्या दर्वे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
- 🛶 उ ६ ८ में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन प्रीयीजनाएँ स्थित है।

उदाहरण :- दुलहस्ती , सतान , बगितहार

- 🛶 यह सिंधु नदी की सबसे वडी शद्ययं नदी 🗞।
- iii) <u>रावी</u>: = वावी नदी का उद्गम शैहताँग दर्रे के पास भी हिमान्यल उदेश में हीता है।
- → हिमायस प्रवेश में इन नदी पर प्रमेश बाँद्य स्थित है।
- → पंजाब में इस नदी पर धीन परियीजना स्थित E।



CAL CENTRE

787815882







AnkitInspiresIndia













India trends

#Nirbhaya2 95.7K posts	•••
2 · Politics · Trending #kolkatahorror Trending with #DoctorsProtest	•••
3 · Politics · Trending #BENGAL_HORROR 11.1K posts	•••
4 · Technology · Trending #MadeByGoogle 9,042 posts	•••
5 · Trending Alleged 54.1K posts	•••
6 · Entertainment · Trending #SaripodhaaSanivaaramTrailer 25.3K posts	•••











Top stories :

Doctors protest against Kolkata doctor's murder >



DH Deccan Herald

Kolkata doctor rape-murder case: All you need to know

10 hours ago



'The way Bengal govt tried to hide ... ': JP Nadda hits out at Mamata Banerjee...



Hindustan Times

Kolkata doctor rape-murder: 4 junior doctors who had dinner with victim...



15 hours ago

ndia Today

Kolkata doctor rape and murder: What happened on the night of incident



1 day ago

The Indian Express

Kolkata doctor rape-murder: Mamata Banerjee says will hand case to CBI if not...



1 day ago

7 hours ago

Doctors in India mourn the loss of a 31-year-old trainee doctor, who was raped and murdered on Friday at RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata, the capital of West Bengal

trt.world/v6f2

TRTW@RLD

Indian doctors halt services in protest over rape and murder

- Doctors demand justice and safety
- Emergency care will continue during the nationwide strike
- West Bengal Chief Minister has given police a deadline to solve the case





Justice for Dr Moumita Debnath



4:21 PM · Aug 13, 2024 · 731.9K Views

इन दिनों देशभर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दिरंदगी की घटना के बाद डॉक्टर सड़कों पर हैं। पश्चिम बंगाल समेत देशभर की तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। इस घटना को लेकर विपक्षी दल भी राज्य सरकार को घेर रहे हैं।

कोलकाता के अस्पताल की घटना क्या है? घटना का खुलासा कैसे हुआ? पुलिस ने मामले में क्या-क्या कार्रवाई की है? विरोध प्रदर्शन करने वालों की मांग क्या है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार, 13 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस की जांच CBI को सौंप दी। राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक CBI को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच सौंपते हुए केवी राजेंद्रन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दुर्लभ मामलों में निष्पक्ष और सही जांच के लिए यह जरूरी है।

हाईकोर्ट ने कहा कि हमने पुलिस को जांच के लिए समय दिया होता, लेकिन मामला अजीब है। घटना के 5 दिनों के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि मामला तुरंत CBI को ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

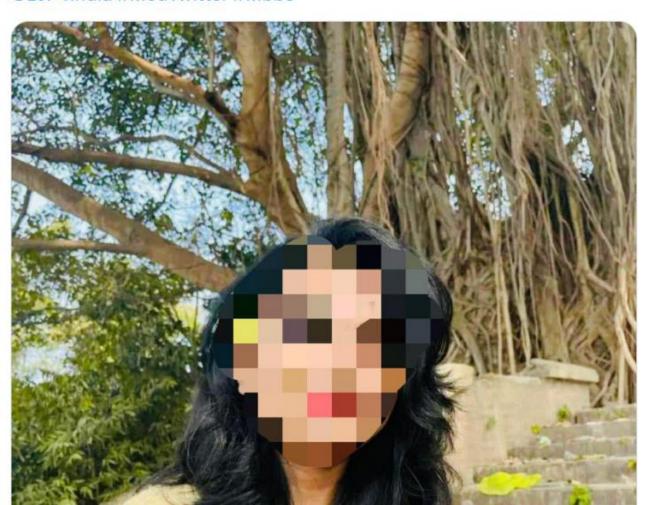


10:07 PM · Aug 9, 2024

Horrific & Unbelievable incident:

Our 2nd year chest Medicine pgt Doctor of RG Kar Medical College, kolkata, West Bengal.

In the morning her body discovered in a way that raped and murder suspected. @MamataOfficial @WBPolice @JPNadda @PMOIndia @BJP4India #MedTwitter #Mbbs



Dr. Jitendra Singh

@DrJsinghRajawat

National President of @official_aimsa (All India Medical Students' Association_AIMSA). instagram.com/national_presi...

RAPE & MURDER?

A Horrific News is coming from RG KAR medical college #Kolkata

Dr Aishwarya (Name Changed)

2nd yr PG resident doctor died in suspicious way in seminar room, where she went to study & Rest during 36 hr duty.

What is happening?

#JusticefordrAishwarya #medtwitter



Indian Doctor

@Indian_doctor

MBBS LUCKNOW!! Sharing Medico's pain/News!

HEALTH ACTIVIST!!, Connecting all MEDICOS
Fighting for RIGHTS of Doctors.

joined Twitter again after 2yrs

🖨 Medical & Health 🛗 Joined September 2018

597 Following **27.7K** Followers

duty... In the morning her body discovered in a way that rape and murder done ... No security in the ward for atleast last 3 yrs as I know ... No sister stays there after 2 am in the ward ..

Our 2nd year pgt , was in on-call duty yesterday and full on well she worked and did dinner together with her juniors at around 2 am yesterday then went for rest and study to the seminar room because no proper on call room is there for taking rest in 36 hr duty... In the morning her body discovered in a way that rape and murder done ... No security in the ward for atleast last 3 yrs as I know ... No sister stays there after 2 am in the ward ... security person sleeps

आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना 8-9 अगस्त की दरमियानी रात की है। मृतक मेडिकल कॉलेज में <mark>चेस्ट</mark> मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्ष डॉक्टर थीं। यह घटना कोलकाता शहर के लालबाजार में घटी जो एक भीड़भाड़ वाला इलाका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थीं। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला।





Platinum Jubilee Building





Here are some steps to becoming a doctor:

- 1. High school: Graduate with strong academics
- 2. College: Attend and finish college, earning a bachelor's degree
- 3. Prerequisite courses: Complete prerequisite courses for medical school
- 4. MCAT: Take the Medical College Admission Test (MCAT) and perform well
- 5. Medical school: Apply to and attend medical school for four years
- 6. Residency: Complete a residency training program that can last 3–7 years, and possibly a fellowship training program in your desired field that can last 1–3 years
- 7. Licensing: Prepare for and pass licensing examinations, and obtain a medical license in your state
- 8. Specialization: Choose a specialization, such as orthopedics, dermatology, or obstetrics and gynecology. You can pursue specialization courses after MBBS, including MD (Doctor of Medicine), MS (Master of Surgery), and PG Diploma courses.

<mark>9 अगस्त</mark>

सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्ध नग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया।







🍪 फिल्म समीक्षा



- 🕨 वीडियो
- 🔊 फोटो गैतरी
- ... राय
- () वेब स्टोरी

🙉 खेत

🔑 पॉडकास्ट

अति आवश्यक

होम तोन ईएमआई कैतकुतेटर,

आयु कैलकुलेटर

कार ऋण ईएमआई कैलकलेट

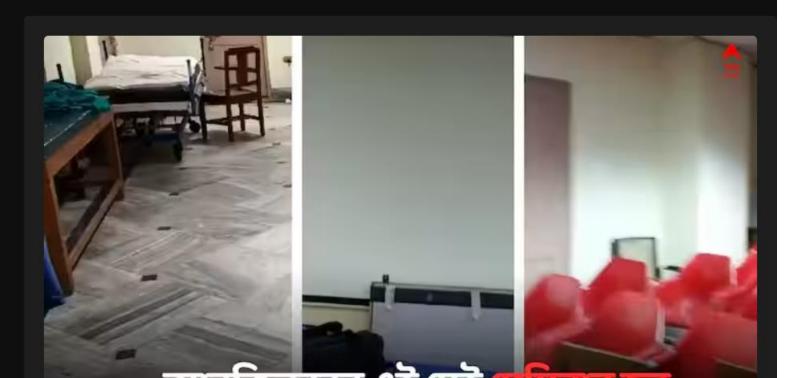
oo बीएमआई कैलकुलेटर

नाइट ड्यूटी के बाद आरजी कर के सेमिनार हॉल में आराम कर रही 'पीड़ित' की 'हत्या', कहां से बरामद हुआ शव?

आरजी कर मेडिकल डॉक्टर्स डेथ मिस्ट्री: नाइट ड्यूटी के बाद आरजी कर के सेमिनार हॉल में आराम कर रहे 'पीड़ित' की हुई 'हत्या', कहां से बरामद हुआ शव?

द्वारा: एबीपी आनंद । अपडेट किया गया: 09 अगस्त 2024 11:16 अपराह्न (IST)













Home

Latest

Movies

Olympics 2024

India

Cricket

V

News / India »Woman Doctor's Body Found Under Mysterious Ci

Woman Doctor's Body Found Under Mysterious Circumstances At Govt Medical College In Kolkata

- Curated By: <u>Pragati Pal</u>
 News18.com
- Last Updated: August 09, 2024, 17:13 IST

The victim, identified as Moumita Debnath (31), a second-year postgraduate student of RG Kar Medical College, was found dead inside the Seminar Hall on the 3rd floor of the campus

'महिला डॉक्टर की हत्या हुई, आत्महत्या नहीं' लालबाजार सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर के यौन शोषण के सबूत मिले. सूत्रों के मुताबिक, नाक, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स पर खून के थक्के पाए गए। आंखों से खून बह रहा था, शरीर पर 10 तरह की चोटें मिलीं।

'महिला डॉक्टर को शरीर के विभिन्न हिस्सों में कई चोटें आई। 2 पैरों से खून बह रहा है, चेहरे, पेट पर चोट है। सूत्रों के मुताबिक शरीर पर नाखून की चोट के निशान मिले हैं।

आरजी कर अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर की रहस्यमय मौत के कारण डॉक्टर हड़ताल पर चले गये.

शव आज सुबह आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल पर सेमिनार कक्ष से बरामद किया गया।

सूत्रों के मुताबिक पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि हमलावर डॉक्टर का परिचित है. 'डॉक्टरों ने रात 2 बजे किया डिनर, आराम करने के लिए सेमिनार रूम में जाएं', आखिर 2 बजे के बाद क्या हुआ? कैसे मरें?

बजा कथा ।डनर, आराम करन का लए सामनार रूम म जाए, आखिर 2 बज के बाद क्या हुआ? कस मर? अभी भी कोहरा है. अस्त-व्यस्त कपड़े, शरीर पर चोटों के निशान, यह शिकायत डॉक्टरों के एक वर्ग की है।

परिजनों ने लगाया रेप और हत्या का आरोप, लीपापोती का आरोप.



महिला डॉक्टर की रहस्यमय मौत के खिलाफ बीजेपी-एसयूसी ने किया विरोध प्रदर्शन. महिला डॉक्टर की मौत कैसे हुई ? अस्पताल की 11 सदस्यीय कमेटी ने जांच की.

अस्पताल में रहस्यमयी मौत को लेकर विरोध में कुछ डॉक्टरों ने की हड़ताल. मुख्यमंत्री ने मृत महिला डॉक्टर के माता-पिता से फोन पर बात की. मुख्यमंत्री ने उचित जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

खबर पाकर पुलिस कमिश्नर, स्वास्थ्य सचिव अस्पताल पहुंचे. पुलिस पूछताछ

करेगी कि उस रात अस्पताल में किसकी ड्यूटी थी।

Protests erupt at Kolkata's RG Kar Medical College over PG trainee's mysterious death; Demands justice and independent autopsy

Sumati Yengkhom & Tamaghna Banerjee / TNN / Updated: Aug 10, 2024, 11:52 IST







FOLLOW US

R G Kar Medical College was in turmoil following the suspicious death of a second-year post-graduate trainee. Fellow students and various groups demanded a thorough investigation, delaying the autopsy for nearly 10 hours. Protests erupted, with some claiming foul play.



R G Kar Medical College was in turmoil following the suspicious death of a second-year post-graduate trainee. Fellow students...

Kolkata: R G Kar Medical College is on the boil again after a second year post-graduate trainee (PGT) was found dead under mysterious circumstances in the hospital during her duty hours around 7.30 am on Friday. While her fellow PGTs, interns, house staff and MBBS students did not let the body be taken away for autopsy till the conditions they had set for the post-mortem and inquiry were met, various organizations, including political wings, also stormed into the medical college to protest the death.

'WON'T RELENT TILL A PROPER PROBE IS DONE'





There were protests on the campus after the body was found around 7.30 am on Friday

We could smell the rat when the college authority tried to discard it as a case of suicide whereas there are all tell-tale signs of sexual abuse and murder

A post-graduate trainee

During the regime of the current principal, there have been various untoward incidents. He should be removed immediately. The autopsy should be conducted by doctors of other hospitals and the process has to be video-graphed

Manas Gumta | SURGERY PROFESSOR AND EX-SECRETARY OF ASSOCIATION OF HEALTH SERVICE DOCTORS lhi 28°C





The initial autopsy of the postgraduate trainee doctor in Kolkata, whose body was found at a state-run hospital on Friday, found that she was "murdered following a sexual assault". The autopsy also ruled out suicide, and a case has since been filed at the Tala Police Station.

"This is not a case of suicide; the woman was murdered following sexual assault," a police officer told news agency PTI.

Here are the details of the autopsy report

The four-page report indicated that there was bleeding from the woman's genital area, along with injury marks on other parts of her body.

"There was bleeding from both her eyes and mouth, injuries over the face and nail. The victim was also bleeding from her private parts. She also has injuries in her belly, left leg... neck, in her right hand, ring finger and... lips," it said.

A senior police official said the crime occurred between 3 and 6 am.

"Her neck bone was also found broken. It seems that she was first strangulated and then smothered to death. We are waiting for the full report of the autopsy, which will help us identify the culprits," he was quoted as saying by PTI.

The Kolkata Police has established a Special Investigation Team (SIT) to investigate the crime, which includes members from the homicide department and other specialised units.

BJP demands CBI probe

Leader of the Opposition and BJP leader Suvendu Adhikari called for a CBI investigation into the death of the 28-year-old postgraduate trainee doctor in Kolkata. He also urged student groups to protest against the state government's inadequate response.

According to PTI, chief minister Mamata Banerjee contacted the woman's parents to promise appropriate action against those responsible. Ruling Trinamool Congress leader Santanu Sen said, "We seek a fair, transparent, and comprehensive investigation into the incident."

"The Mamata Banerjee administration has always prioritised the safety and security of women," said Sen, who is a former national president of the Indian Medical Association.



10 अगस्त की सुबह महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में <mark>संजय रॉय</mark> नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अज्ञात पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की गतिविधियां काफी संदिग्ध हैं और ऐसा लगता है कि वह सीधे तौर पर अपराध में शामिल है। आरोपी ब्लूट्रथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया था जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था। दोपहर को एसीपी मुरली धर ने बयान जारी कर कहा कि यह हत्या और दुष्कर्म का मामला है। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है। वहीं इसी दिन शाम को कोलकाता के सीपी विनीत कुमार गोयल ने बताया कि पीड़िता का पोस्टमॉर्टम कर लिया गया है और इसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। सभी सब्तों को जांचा परखा गया है और इसी आधार पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है।



पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे

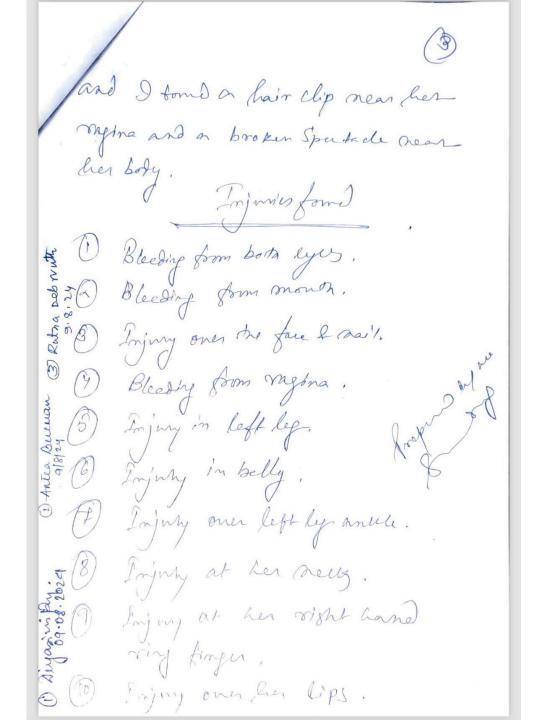
सोमवार को कोलकाता पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के हाथ और चेहरे पर काटने के निशान मिले हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके चश्मे के कांच के टुकड़े आंखों में घुस गए थे. इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता का सिर दीवार पर भी पटका था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई थीं. बताया जा रहा है कि आरोपी ने दीवार पर सिर पटकते समय पीड़िता का मुंह दबा दिया था, जिससे उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं. यही नहीं, दिरदगी की हद तो तब पार हो गई जब आरोपी ने ट्रेनी डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या कर दी. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों को उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे रेप की पृष्टि होती है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेनी डॉक्टर पर उस वक्त वार किए गए थे जब वह जिंदा थी. उसके प्राइवेट पार्ट पर लगी चोटों से संकेत मिलता है कि उसके साथ रेप हुआ था. बर्बरता से मारपीट करने और यौन उत्पीड़न के बाद आरोपी ने ट्रेनी डॉक्टर की गला घोंटकर और दम घोंटकर हत्या कर दी. रिपोर्ट में मौत का समय शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच बताया गया है.

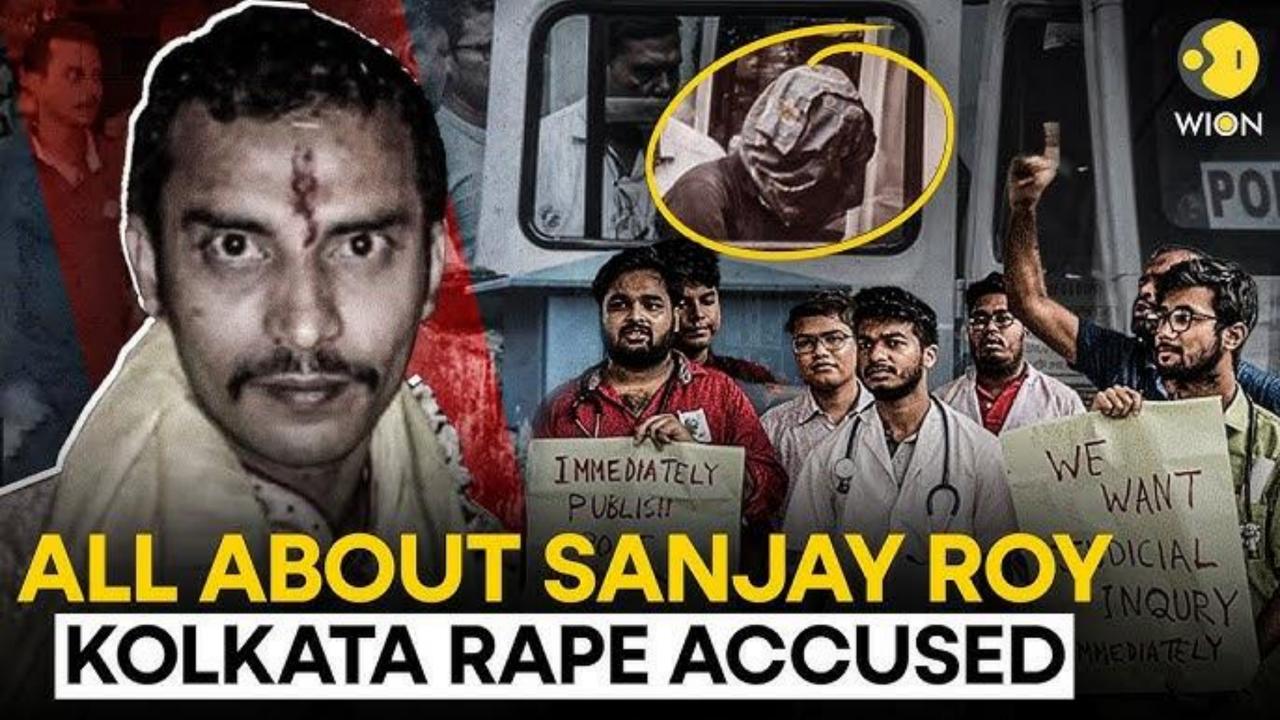
कोलकाता रेप-मर्डर केस

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 5 खुलासे

- अबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के
 कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव
 पाया गया।
- ्र चिल्लाने से रोकने के लिए नाक-मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया।
- सिर को दीवार से सटा दिया गया, जिससे चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं।
- इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था।
- चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद तो बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था।







कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं हत्या के आरोप में गिरफ्तार दिरंदे संजय रॉय की पहचान शराबी और पोर्न एडिक्ट के रूप में हुई है। विशेष जांच दल (SIT) का मानना है कि 9 अगस्त की सुबह अपराध करते समय वह शराब के नशे में था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, तो वह शांत और सहज दिखाई दिया। उसने अपराध करने की बात स्वीकार की। जांच में यह भी पता चला कि उसके मोबाइल फोन में कई पोर्नोग्राफिक क्लिप थे।

संजय रॉय की कई शादियां असफल रहीं। पुलिस को रॉय के मोबाइल फोन में कई पोर्न मिला, जिसकी पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वालंटियर के तौर पर भूमिका के कारण अस्पताल के कई विभागों तक उसकी आसान पहुंच थी। 'द टेलीग्राफ' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रॉय ने पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया कि कथित तौर पर युवा डॉक्टर के साथ क्रूरता करने से कुछ घंटे पहले वह गुरुवार रात को दो बार रेड-लाइट एरिया में गया था।

आरोपी संजय को लेकर अब तक ७ बड़े खुलासे

संजय रॉय (33 साल) कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों का करीबी है। उसने 2019 में सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस जॉइन की। इसके बाद वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा।

पुलिस अधिकारियों का करीबी होने के कारण अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। किसी में भी अस्पताल के अंदर उसकी मनमानी को रोकने की हिम्मत नहीं थी। सिविक वॉलंटियर के तौर पर संजय को हर महीने 12 हजार रुपए मिलते थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय आरजी कर अस्पताल में पेशेंट को भर्ती कराने के नाम पर पैसा वसूलने वाले रैकेट का भी हिस्सा था। अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर वह दूसरे नर्सिंग होम में बेड अरेंज करवाने के लिए मोटी फीस लेता था।

वह कोलकाता पुलिस लिखी टीशर्ट पहनकर घूमता था। उसने अपनी बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। वह अपने आपको पुलिसकर्मी ही बताता था। कई अन्य वॉलंटियर उसे पुलिस ही मानने लगे थे। पुलिस में संजय की पहुंच कोलकाता पुलिस की चौथी बटालियन के बैरक तक थी, जहां वह रहता था। रेप-मर्डर के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया। उठने के बाद उसने अपने कपड़े तक साफ किए थे। उसके जूते पर खून के धब्बे भी मिले।

संजय को पोर्न देखने की लत थी। उसके फोन में कई हिंसक अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस इस बात से हैरान है कि संजय इतने वीभत्स पोर्न कैसे देखता था। उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

आरोपी 4 शादियां कर चुका है। हिंसक व्यवहार के कारण सभी पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं। चौथी पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी। पड़ोसियों ने बताया कि उसके घर से अक्सर लड़ाई-झगड़े की आवाजें आती रहती थीं। <mark>सबूत मिटाने की कोशिश</mark> जांच दल के अनुसार, घटना के बाद उसने अपने कपड़े धोकर सबूत मिटाने का प्रयास किया।

सीसीटीवी फुटेज में रॉय को सुबह 4 बजे आपातकालीन भवन में प्रवेश करते और 40 मिनट बाद बाहर निकलते हुए देखा गया।

<mark>9 अगस्त की रात क्या हुआ?</mark>

गला घोंट दिया।

रूम में खाना खाया। जबिक वे नीरज चोपड़ा को भारत के लिए रजत पदक जीतते हुए देख रहे थे। खाने के बाद उसके सहकर्मी चले गए। इसके बाद पीड़िता ने पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह 3 बजे, उसे कमरे में सोते हुए देखा गया। सुबह 4 बजे के आसपास आरोपी सेमिनार हॉल में घुसा और उसका यौन उत्पीड़न किया। जब उसने विरोध करने का प्रयास किया, तो अपराधी ने उसका

9 अगस्त को आधी रात के बाद डॉक्टर और चार सहकर्मियों ने खाना मंगवाया और सेमिनार







After a nation wide strike request from @FordaIndia we at PGIMS organised a symbolic protest for 2 hours for the justice of our fallen soldier in Kolkata, West Bengal. I request all the journalists to look into this horrible rape case and please support the doctors and educate our cause to the public. This grave incident is no less than Nirbhaya case and yet all over India there hasn't been any solidarity to our fraternity.

@rohini_sgh



Mohammed Zubair and 6 others

2:39 PM · Aug 12, 2024 · 20.9K Views

VIDEO | Angered resident doctors of Safderjung Hospital in Delhi protest against Bengal doctor's rape-murder.



11:42 AM · Aug 12, 2024 · **5,383** Views



In protest against the sexual assault and rape of a post-graduate medical student, citizens, medical students and doctors hit the streets in #Kolkata, marching from College Street to RG Kar Medical College and Hospital.

Report on @ndtv @ndtvindia & NDTV.com



Last edited 6:18 PM · Aug 12, 2024 · 320 Views

देशभर में जारी विरोध के बीच, कोलकाता के सीपी गोयल (Kolkata Police Commissioner) ने घटना वाले अस्पताल का दौरा किया और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात की। सीपी ने जानकारी दी कि उन्होंने पीड़िता के परिवार से भी मुलाकात की और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उन्हें सौंप दी गई। कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि घटना की रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। सीपी गोयल ने बताया कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया है। इसी दिन बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किए।

<mark>12 अगस्त</mark>

देशभर में डॉक्टरों का विरोध और तेज हो चुका था। इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र से मुलाकात की। एसोसिएशन के महासचिव सर्वेश पांडे ने कहा कि उनकी मांग है कि मामले की सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक समिति बनाई जाए। पांडे ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक देशव्यापी हड़ताल जारी रहेगी। देशभर के तीन लाख से ज्यादा डॉक्टर विरोध में शामिल हो गए हैं।

ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने सोमवार (12 अगस्त) को देशभर में हड़ताल की घोषणा की। FORDA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखे लेटर में कोलकाता की घटना को रेजिडेंट डॉक्टर समुदाय के इतिहास में हुआ शायद सबसे बड़ा उपहास बताया।

FORDA ने केंद्र से <mark>मामले की CBI जांच</mark> कराने और <mark>आरजी कर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की</mark> है। उन्होंने यह आश्वासन भी मांगा है कि <mark>प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा।</mark>

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लेटर लिखकर <mark>डॉक्टरों के</mark> खिलाफ हमलों और हिंसा <mark>को रोकने के लिए कानून बनाने और अस्पतालों को सेफ जो घोषित करने की</mark> मांग की है।

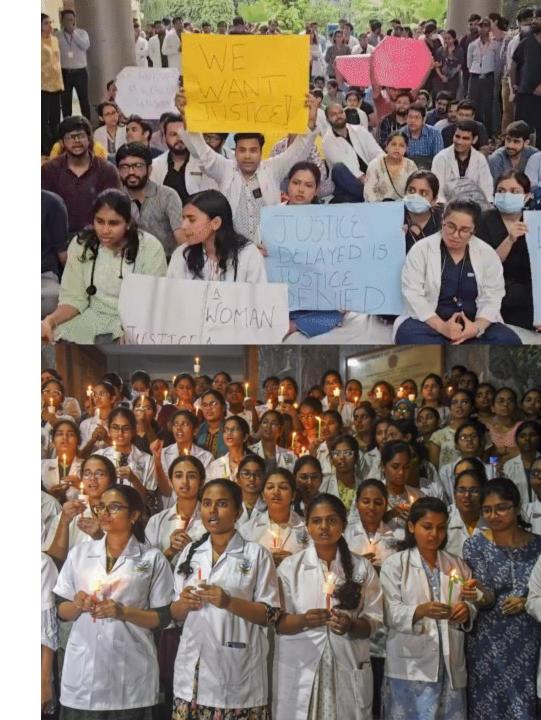
इसके अलावा <mark>सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पुलिस कैंप और पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती</mark> <mark>करने की भी मांग</mark> की गई है। IMA ने बंगाल सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा

दिलाने की मांग की। इसके अलावा <mark>डॉक्टरों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम</mark>

उठाने को कहा है।

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की मांगें...

- आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उन पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए।
- **2** घटना का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस बर्बरता या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक विरोध करने के उनके अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।
- मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, इस मामले में जल्द से जल्द न्याय हो।
- केंद्र सरकार को सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए, जिससे इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।
- के सेंट्रल हेल्थकेयर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में तेजी लाने के लिए मेडिकल एसोसिएशन और कम्युनिटी वाली एक्सपर्ट कमेटी का तत्काल गठन किया जाना चाहिए।





UNITED DOCTORS FRONT ASSOCIATION

Registered under Section 8 Act . 2013 under the Ministry of Corporate Affairs

X:@udfaindia

Web: http://www.udfa.in M:udfindia2022@gmail.com

f:@udfindia2022 @:udfa india

National Chairman Dr. Deepankar Chaudhary

Chief Advisors

Dr.Ankit Om

Prof.(Dr.)Raiveer Arva

Dr.Sanjeev Chaudhary

Dr Raishekhar Yaday

Dr.Jitendra Singh

Dr Rahul Choudhary National Vice President

National Spokesperson

National Joint Secretary

Dr.Heera (CG State President)

Dr.Shubham Soni(MH State President)

Dr.Sanket Site(JDA Bhopal President)

Dr.Raiesh Kumawat (JARD SMS)

Dr. Vivek Pandey (RTI Activist)

Dr Shiyani Purohit (Head)

Dr.Subhash Sharma(PGI Rohtak)

Dr.Jatin Prajapati (Secy, Udaipur)

Dr. Aanchal Kataria (Secretary)

Dr.A.Prashant(CG State Secretary

Dr. Vinod Bagra (Raj. State Secy)

Dr. Navan Jain (JDA Indore Presid

Dr.Karanveer (PB State President)

Dr. Hritwik Bhardwaj (Etawah, UP)

Dr.Deepankur Maggo (NCR Regio

Dr. Yogendra (CG State Secretary)

Dr.Ravi Soni (MP MO Secretary)

Dr. Ashik S (Tamilnadu State President

Dr. Vidhit Baswani (CIP Ranchi, JH)

Dr Sumit Gunta (CG State IS)

Dr. Titir Biswas (CG State VP)

Dr.Sunny Chaudhary (GTE

Dr.Himanshu Yaday (UP)

Dr. Deenakram Ahirwar (Ujiair

Dr. Ashu Awasthi (UK)

Dr.Preethi (Tamilnadu)

Dr.Anil (CG)

East Zone Coordinator

West Zone Coordinator

Dr.Saumil Shah (GJ)

JR Representative

Dr. Akhil Garg (ESIC)

Dr. Prabhu Malhotra (UP)

South Zone Coordinator

Dr. Abu Hurera (Karnataka)

Dr Ashish Mahant (Rajasthan) Dr.Gaurav Raj (Jaipur)

Dr.Samyak Bansal(Jaipur)

Dr.Akshit (PGI Chandigarh)

Central Zone Coordinator

Dr.Abhimanyu Agrawal(MP)

North Zone Coordinator Dr.Prajwal (PGI Rohtak, Secretary)

Dr.Swati Dangi (Safdarjung,Delhi)

Dr.Asgar Ali

Legal Cell

Academic Cell

Dr.Anshul Goel

Social & IT Cell

Dr Vedant Shekhar

National Coordinato

Dr.Nirmalya Mohapatra

National President Dr. Lakshva Mittal +91 9549395092

Shri J.P. Nadda Ji

National General Secretary Dr. Arun Kumar +91 9671675396

Hon'ble Chief Patron Dr. Amarinder Singh Malhi

Ref No. - udfindia/24/12

Date:- 12-08-2024

Hon'ble Union Minister for Health & Family Welfare Government of India New Delhi

Shri Amit Shah Ji Hon'ble Union Minister of Home Affairs Government of India New Delhi

Subject: Nationwide Protest Initiation and Demand for CBI Enquiry and Central Protection Law for Healthcare professionals

Respected.

The United Doctors Front Association (UDFA) is deeply dismayed by the lack of action following our ultimatum issued on 10th August 2024, regarding the brutal murder of Dr.Moumita Debnath, a second-year postgraduate student at R.G. Kar Medical College, Kolkata, West Bengal

The horrific nature of this crime, committed within the confines of an educational institution, underscores the pressing need for immediate and decisive measures to ensure the safety and security of medical professionals across the nation.

Despite our clear demands for justice and enhanced safety measures, the authorities have failed to respond adequately within the stipulated 48-hour period.

In light of this continued inaction, UDFA will be staging a nationwide protest commencing from 13th August 2024. This protest is a necessary step to express our collective outrage and to press for the fulfillment of our demands, which include:

- 1. A fair and impartial CBI investigation into the circumstances surrounding Dr.Debnath's death, ensuring that justice is delivered without further delay.
- 2. The immediate introduction and implementation of a central law to protect healthcare workers from violence, ensuring their safety in all medical institutions and workplaces across the country.
- 3. The declaration of hospitals and healthcare establishments as 'safe zones' with clearly defined security measures, including the establishment of police camps in major government hospitals and mandatory security protocols for large private.
- 4. The installation of CCTV cameras at all vulnerable points within healthcare facilities to deter potential acts of violence and ensure rapid response capabilities.

Chief Advisors

Dr.Ankit Om

Prof.(Dr.)Rajveer Arya

Dr.Sanjeev Chaudhary

Dr.Nirmalya Mohapatra

National Vice President

National Spokesperson

National Joint Secretary

Dr. Heera (CG State President)

Dr.Swati Dangi (Safdarjung.Delhi)

Dr.Shubham Soni(MH State President

Dr.Sanket Site(JDA Bhopal President)

Dr.Rajesh Kumawat (JARD SMS)

Dr. Vivek Pandey (RTI Activist)

Dr.Shivani Purohit (Head)

Dr.Subhash Sharma(PGI Rohtak)

Dr.Jatin Prajapati (Secy, Udaipur)

Dr.A.Prashant(CG State Secretary)

Dr. Prajwal (PGI Rohtak, Secretary)

Dr.Karanveer (PB State President)

Dr. Hritwik Bhardwaj (Etawah, UP)

Dr.Deepankur Maggo (NCR Region)

Dr. Yogendra (CG State Secretary)

Dr.Ravi Soni (MP MO Secretary)

Dr. Ashik S (Tamilnadu State President)

Dr Vidhit Baswani (CIP Ranchi IH)

Dr.Sumit Gupta (CG State JS)

Dr. Titir Biswas (CG State VP)

Dr.Sunny Chaudhary (GTB

Dr.Himanshu Yadav (UP)

Dr.Deepakram Ahirwar (Ujjain)

Dr.Ashu Awasthi (UK)

Dr.Prabhu Malhotra (UP)

South Zone Coordinator

Dr.Abu Hurera (Karnataka)

Dr.Preethi (Tamilnadu)

East Zone Coordinator

West Zone Coordinator

Dr Saumil Shah (GD)

JR Representative

Dr. Akhil Garg (ESIC

Dr.Anil (CG)

Dr. Ashish Mahant (Rajasthan)

Dr. Vinod Bagra (Raj. State Secy) Dr.Nayan Jain (JDA Indore Presider

Dr.Abhimanyu Agrawal(MP)

North Zone Coordinator

Dr.Gaurav Raj (Jaipur)

Dr.Samyak Bansal(Jaipur)

Dr.Akshit (PGI Chandigarh)

Central Zone Coordinator

Dr.Raishekhar Yaday

Dr.Jitendra Singh

Dr.Rahul Choudhary

Dr. Asgar Ali

Academic Cell

Dr. Anshul Goel

Social & IT Cell Dr. Aanchal Kataria (Secretary)

Dr. Vedant Shekhar

National Coordinator

UNITED DOCTORS FRONT ASSOCIATION

Registered under Section 8 Act , 2013 under the Ministry of Corporate Affairs

Web: http://www.udfa.in M:udfindia2022@gmail.com X:@udfaindia

f:@udfindia2022 @:udfa india

National Chairman Dr. Deepankar Chaudhary **National President** National General Secretary Dr. Lakshva Mittal Dr. Arun Kumar +91 9549395092

+91 9671675396

Hon'ble Chief Patron Dr. Amarinder Singh Malhi

Ref No. - udfindia/24/12 Date: - 12-08-2024

The continued neglect of the safety of medical professionals not only jeopardizes the lives of those who serve on the frontlines of healthcare but also erodes public trust in our healthcare system. We urge the government to reconsider its stance and engage in meaningful dialogue with UDFA to address these critical issues. The medical fraternity cannot continue to operate under the constant threat of violence, and we demand the necessary legal and security measures be implemented without further delay.

Along with UDFA, the All India Medical Students Association (AIMSA) is also extending its full support, mobilizing medical students across the nation to join and participate in the protest

Formation of an Expert Committee: An expert committee comprising representatives from the medical community and associations must be formed to speed up ratifying the Central Healthcare Protection Act. This is an urgent necessity and should be completed without delay with a tentative timeline for ratification.

We hope that you will give due consideration to our demands in the interest of safeguarding the lives and well-being of healthcare workers across the nation. Failure to meet our demands will only escalate our protest actions until our voices are heard and our concerns are addressed.

National President

Dr. Lakshya Mittal

National General Secretary

Dr. Arun Kumar



In response to the tragic incident involving the alleged sexual assault and murder of a 31-year-old trainee doctor in Kolkata, the National Commission for Women has taken suo moto cognizance and formed an Inquiry Committee. The committee, led by Ms. Delina Khongdup, Member NCW will look inquire about the circumstances, meet with all relevant parties, and recommend measures to prevent such incidents in the future.

@KolkataPolice

4:29 PM · Aug 11, 2024 · 816 Views



#WATCH | Rape-murder of a PG trainee woman doctor in Kolkata | Principal of RG Kar Medical College & Hospital, Prof. (Dr.) Sandip Ghosh resigns from his post.

He says, "...I am getting defamed on social media...The deceased doctor was like my daughter. As a parent, I resign...I don't like that this should happen to anyone in future..."



10:45 AM · Aug 12, 2024 · 199.6K Views

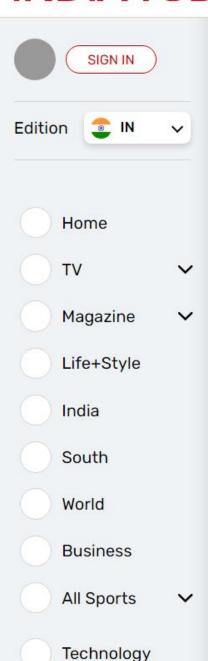
डॉक्टरों और एक हाउस स्टाफ से पूछताछ, अदालत में याचिका

कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार में तीन जूनियर डॉक्टरों और एक हाउस स्टाफ को तलब किया गया। ये सभी घटना की रात ड्यूटी पर थे। इसी दिन पश्चिम बंगाल भाजपा नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौस्तव बागची ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों और रेस्ट रूम में उचित सुरक्षा के साथ सीसीटीवी लगाने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री का बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम

मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममत बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर रविवार तक पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो हम केस को सीबीआई को सौंप देंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा ने सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

INDIA TODAY



News / Law / Kolkata doctor rape-murder: Plea filed at Calcutta High Court seeking CBI probe

Kolkata doctor rape-murder: Plea filed at Calcutta High Court seeking CBI probe

Four Public Interest Litigations (PIL) at Calcutta High Court has sought a proper investigation by the Central Bureau of Investigation (CBI) into the Kolkata doctor rape and murder case.





Share

ADVERTISEMENT

Aug 12, 2024



Calcutta HC orders CBI probe into RG Kar Hospital doctor's rape-murder case

TOI City Desk / TIMESOFINDIA.COM / Updated: Aug 13, 2024, 16:04 IST







FOLLOW US 💏

The Calcutta High Court ordered a CBI investigation into the rape and murder of a trainee doctor at RG Kar Medical College and Hospital. The police were instructed to hand over all relevant documents. The trainee's parents and multiple PILs sought a court-monitored probe. Nationwide, resident doctors protested, leading to



Resident doctors at government hospitals nationwide have been protesting over the incident since Saturday. (PTI Photo)

NEW DELHI: Amid the growing nationwide outrage, the Calcutta high court on Tuesday ordered a CBI probe into the rape and murder of a trainee doctor at city's RG Kar Medical College and Hospital, news agency ANI reported.

The court also asked the police to hand over all the documents related to the case to the central probe agency immediately.

The HC also urged the agitating doctors to call off ceasework saying that have a 'pious obligation' on

the part of doctors to treat their patients.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार, 13 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस की जांच CBI को सौंप दी। राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक CBI को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच सौंपते हुए केवी राजेंद्रन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दुर्लभ मामलों में निष्पक्ष और सही जांच के लिए यह जरूरी है।

हाईकोर्ट ने कहा कि हमने पुलिस को जांच के लिए समय दिया होता, लेकिन मामला अजीब है। घटना के 5 दिनों के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि मामला तुरंत CBI को ट्रांसफर किया जाना चाहिए।





हम प्रेस का मुंह नहीं बंद कर सकते। हादसा बहुत वीभत्स है। डॉक्टरों का अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सही है। वे आहत हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा- प्रिंसिपल ने इस्तीफा क्यों दिया, यह समझना

मुश्किल

हाईकोर्ट ने घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ संदीप कुमार घोष के इस्तीफे और दूसरी कॉलेज में उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यह जानकर दुख होता है कि घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन और तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष सक्रिय नहीं थे।

प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनके इस्तीफे पर क्या आदेश जारी किए गए थे। बल्कि इस्तीफे के 12 घंटे के भीतर 12 अगस्त को उन्हें एनएमसी, कोलकाता का प्रिंसिपल बना दिया गया। यह समझना मुश्किल है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने की क्या जल्दी थी।



हाईकोर्ट बोला- प्रिंसिपल को छुट्टी पर भेजो या हम ऑर्डर पास करें

हाईकोर्ट ने डॉ संदीप कुमार घोष को छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि उनको लंबी छुट्टी पर भेजिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें ऑर्डर पास करना होगा। उन्हें कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। उनको कहिए घर पर रहें।

कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि पुलिस ने डॉ संदीप घोष से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच में कुछ मिसिंग है। जब डॉ. संदीप घोष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था, तो उन्हें इस्तीफे के तुरंत बाद दूसरे मेडिकल कॉलेज में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? उनसे सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ।

Important Administrative Contacts

DESIGNATION	NAME
Principal	Prof. (Dr.) Sandip Ghosh
Medical superintendent cum vice principal	Prof. (Dr.) Sanjay Vashisth
Dean of student affairs	Prof. (Dr.) Bulbul Mukhopadhyay
Additional Medical Superintendent	Dr. (Major) Dwaipayan Biswas
Deputy superintendent (nm)	Sri Anindya Ray
Deputy superintendent (nm)	Sri Arindam Mukherjee
Deputy superintendent (nm)	Sri Surajit Sen
Assistant superintendent (nm)	Sri Arkendra Mohan Sinha
Assistant superintendent (nm)	Sri Pushon Banerjee
Assistant superintendent (nm)	Smt Debalina Sengupta
Assistant superintendent (nm)	Sri Dwaipayan Biswas
Assistant superintendent (nm)	Smt Swati Bhowmick
Assistant superintendent (nm)	Smt Sucharita Sarkar

कोर्ट रूम लाइव...

- विकास रंजन भट्टाचार्य (डॉक्टर के पेरेंट्स के वकील): हमें पहले बताया गया कि वह (पीड़ित) बीमार थी। फिर कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। पेरेंट्स को अस्पताल बुलाया गया। उन्हें तीन घंटे तक बैठाए रखा गया। पुलिस ने उन्हें मामला सेटल करने को कहा। सीएम का कहना है कि कुछ दिनों बाद CBI को मामला सौंपेंगे। तब तक तो सबूत ही मिटा दिए जाएंगे।
- चीफ जिस्टिस शिवगणनम: अगर यह सच है कि किसी ने माता-िपता को यह बताया कि यह बीमार थी और िफर आत्महत्या की, तो कहीं न कहीं चूक हुई है।
- विकास रंजन भट्टाचार्य (डॉक्टर के पेरेंट्स के वकील): यह रिकॉर्ड में है कि पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया है।
- राज्य सरकार: ऐसे सभी मामले अननेचुरल डेथ के रूप में दर्ज किए जाते हैं।
- कोर्ट: पीड़ित सिस्टम का हिस्सा थी। उसके प्रित कुछ संवेदना दिखाना चाहिए थी। उन्होंने अपना जीवन सिस्टम के लिए काम करते हुए बिताया। अगर यह सच है कि उनके पेरेंट्स को अस्पताल में इंतजार कराया गया और गुमराह किया गया तो प्रशासन उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप मृतक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते।

- कोर्ट: प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद छोड़ दिया था। सरकार ने 12 घंटे के भीतर उन्हें दूसरी नियुक्ति पत्र का रिवॉर्ड दिया। फिर आशंका है कि जांच में समय बर्बाद होने पर कुछ गलत हो जाएगा।
- विकास रंजन भट्टाचार्य (डॉक्टर के पेरेंट्स के वकील): उन्हें केस डायरी देने के लिए कहिए। ऐसा पहले भी हो चुका है। मौजूदा सीपी पहले भी जांच में गड़बड़ी कर चुके हैं। दोपहर 2 बजे केस डायरी लाई जाए।
- राज्य सरकार: हम कल एक रिपोर्ट दिखाएंगे।
 कोर्ट: हम आपको समय देंगे लेकिन आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस बीच कुछ भी गलत नहीं
- <mark>राज्य सरकार</mark>: एसीपी-I देखरेख कर रहे हैं।
- विकास रंजन भट्टाचार्य (डॉक्टर के पेरेंट्स के वकील): फिर उनका ट्रांसफर हो जाएगा।
- कोर्ट: प्रिंसिपल काम नहीं करेंगे। उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने दिया जाए। नहीं तो हम ऑर्डर देंगे।
- कोर्ट: प्रिंसिपल ने बयान दिया?
- राज्यः नहीं। हम ले लेंगे।

होगा?

• <mark>कोर्टः</mark> ये क्या है? उनका बयान सबसे पहले होना चाहिए। वे कानून से ऊपर नहीं हैं। यह कैसे हो गया। आप

उन्हें क्यों बचा रहे हैं? उन्हें सच बोलने दीजिए। यहां कुछ चूक हुई है।



This is an abomination! West Bengal is in flames with rage, yet Mamata Banerjee and her lapdog Kolkata Police are knee-deep in a filthy coverup of a brutal rape and murder!

RG Kar Medical College authorities are smashing down walls, obliterating crucial evidence—evidence that could have exposed the vile monsters who committed this heinous act.

Is this the 'new normal' in Mamata's Bengal, where rapists and murderers are shielded because they're connected to TMC's rotten elite?

The so-called 'renovation' in the Chest Medicine Dept is nothing but a blatant, disgusting attempt to erase the crime scene, all to protect the guilty who are rumored to be relatives of TMC leaders.

Mamata Banerjee, your hands are stained with the blood of innocent women! Your silence, your apathy, and your disgraceful complicity make you just as guilty! Bengal has become a hellscape under your watch, where women are prey and justice is a joke. Enough is enough—Bengal demands accountability now!





NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of a junior woman doctor in mysterious circumstances at the state-run RG Kar Medical College & Hospital in Kolkata, West Bengal. May like to refer to the press release at: nhrc.nic.in/media/press-re...

...



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, INDIA

SUO MOTU COGNIZANCE

- NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of a junior woman doctor in mysterious circumstances at the state-run RG Kar Medical College & Hospital in Kolkata, West Bengal
- Takes a serious view of the reported allegations about sexual assault and murder
- Issues notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, West Bengal calling for a detailed report in the matter within two weeks



#WATCH | Delhi: A meeting between the delegation of the Federation of Resident Doctors Association (FORDA) and Union Health Minister JP Nadda concludes.



10:34 PM · Aug 13, 2024 · **27.4K** Views



#WATCH | Delhi: After meeting Union Minister JP Nadda, Federation of Resident Doctors' Association President Aviral Mathur says, "We just met Union Minister JP Nadda at his residence and presented our reformulated demands and before him... He assured us that he would provide a safe working environment for doctors. He has assured us that our demands would be addressed in a time-bound manner. A committee would be formed and we would be a part of it... All our demands have been accepted, hence, FORDA is calling off the strike..."







Union Health Minister, Shri @JPNadda met with the Federation of Resident Doctors Association (@FordaIndia) delegation today.

He welcomed their decision to call off the strike in the public interest and assured them that the Ministry of Health & Family Welfare will address all their concerns to ensure a safer and better work environment.



A PMO India and 8 others

Top stories :

The Economic Times

Kolkata doctor rape-murder case: Doctors' union calls off strike after meeting Union Minister Nadda 🕢



4 hours ago

NDTV

Doctors' Bodies Differ On Calling Off Strike Over Kolkata Rape-Murder



5 hours ago



"No Assurance...": Key Doctors' Body Says Strike Over Kolkata Rape To



6 hours ago



कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के मामले में दो दिन से जारी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) की हड़ताल मंगलवार शाम को खत्म हो गई। FORDA के कुछ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, इसलिए वे हड़ताल खत्म कर रहे हैं।

हालांकि देश के कई अन्य अस्पतालों और दूसरे एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कहा है कि वे हड़ताल जारी रखेंगे। इसमें AIIMS, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोएिशन (FAIMA) के शामिल हैं। इनका कहना है कि जब तक डॉक्टरों पर हमले रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के डॉ. ध्रुव चौहान हड़ताल खत्म करने पर FORDA की आलोचना की। उन्होंने कहा कि <mark>ज्यादातर मेडिकल फ्रेटरनिटी इसके विरोध में है। अब हड़ताल खत्म करने का मतलब होगा कि फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर्स को शायद कभी इंसाफ न मिले। इसलिए सेंट्रल हॉस्पिटल्स अपनी हड़ताल जारी रखेंगे।</mark>

12:15 AM · Aug 14, 2024

The strike will be continued. Doctors across India demanding a Central Protection Act to prevent such horrific acts in our nation. We urge everyone to support this crucial cause. No more Nirbhayas in our country. Residents, rest assured, WE STAND WITH YOU! #DoctorsStrike

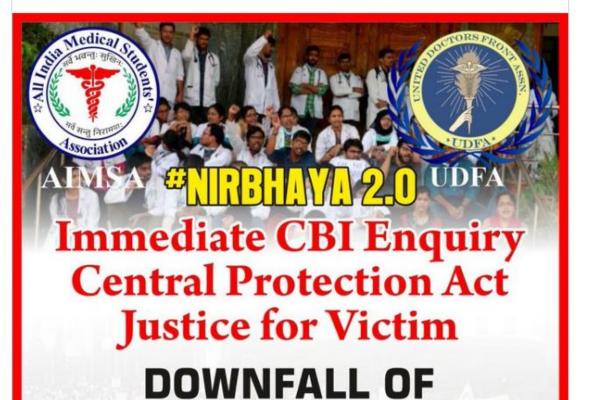


ALL INDIA MEDICAL STUDENTS' ASSOCIATION @official aimsa · 15h

Team @official_aimsa & @udfaindia staging a nationwide protest from 13-8-24 #demands:

- 1. Immediate CBI Enquiry
- 2. Implementation of Central Protection Act ...

Show more





RESIDENT DOCTORS ASSOCIATION

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI-110029.



(Regd. under Societies Registration Act XXI of 1860: Regn. No. S/9715/Distt. South/2019)



Address: Ground Floor, Hostel 8, AlIMS, New Delhi - 110029 Email: aiimsrdapresident@gmail.com, rdaaiimsdelhi@aiims.edu Ph: +91 8700840075, +91 96509 41820 Logon to: rdaaiims.org

President

Dr. Indra Shekhar Prasad

Vice President

Dr. Harshith Gowda R Dr. Suvrankar Datta

General Secretary

Dr. Raghunandan Dixit

Joint Secretary

Dr. Ayush Jain Dr. Mehul K

Treasure

Dr. Mohit Chowdhury

Sports & Gymkhana Secretary

Dr. Nitin Chauhan

SR Representative

Dr. Bhawna Arora

SD Representative

Dr. Arkadipta Mukherjee

JR Representative

Dr. Prakalp Gupta

Dr. Ravneet Singh

Female Doctors Representative

Dr. Amisha Maroo Dr. Richa Mishra

Intern Representative

Dr. Ankit Kumar

Ref No: 57/RDA2024-25

Date:

13/08/24

PRESS RELEASE

Today at 7:10 PM, the residents and undergraduates of AllMS, New Delhi convened a general body meeting at the JLN Auditorium. The AllMS community reaffirmed their demand for the implementation of the Central Protection Act and continued their support for the doctors of RG Kar MC&H. It was unanimously decided that AllMS resident doctors including foreign national and sponsored candidates, fellows, and undergraduates would continue with their indefinite strike, including the suspension of academic activities, elective OPDs, ward, and OT services. However, emergency services, ICUs, emergency procedures, and emergency OT will remain operational.

The following resolutions were agreed upon:

- 1. Written assurance for the implementation of the Central Protection Act.
- CBI Inquiry: The general body welcomed the High Court's verdict and called for a fair and transparent investigation.
- Suspension of the former Principal pending inquiry, along with a public apology for offending the sentiments of the victim and the medical community.
- 4. Granting martyr status to the victim and naming a building/library at RG Kar MC&H hospital in her honor.
- 5. Providing adequate compensation to the doctor's family.
- Condemnation of the police assault on the protesting resident doctors and a call for strict action against the officers involved.

The general body emphasized that the implementation of the Central Protection Act is urgently needed. Despite the Act's introduction, no decisive action has been taken to address the ongoing attacks on doctors.

Page 1/2



RESIDENT DOCTORS ASSOCIATION

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI-110029.



13/08/24

Date:

(Regd. under Societies Registration Act XXI of 1860: Regn. No. S/9715/Distt. South/2019)

Ref No: 57/RDA2024-25



Address: Ground Floor, Hostel 8, AlIMS, New Delhi - 110029
Email: aiimsrdapresident@gmail.com, rdaaiimsdelhi@aiims.edu
Ph: +91 8700840075, +91 96509 41820
Logon to: rdaaiims.org

President

Dr. Indra Shekhar Prasad

Vice President

Dr. Harshith Gowda R Dr. Suvrankar Datta

General Secretary

Dr. Raghunandan Dixit

Joint Secretary

Dr. Ayush Jain Dr. Mehul K

Treasurer

Dr. Mohit Chowdhury

Sports & Gymkhana Secretary

Dr. Nitin Chauhan

SR Representative

Dr. Bhawna Arora

SD Representative

Dr. Arkadipta Mukherjee

JR Representative

Dr. Prakalp Gupta

Dr. Ravneet Singh

Female Doctors Representative

Dr. Amisha Maroo Dr. Richa Mishra

Intern Representative

Dr. Ankit Kumar

PRESS RELEASE

Today at 7:10 PM, the residents and undergraduates of AllMS, New Delhi convened a general body meeting at the JLN Auditorium. The AllMS community reaffirmed their demand for the implementation of the Central Protection Act and continued their support for the doctors of RG Kar MC&H. It was unanimously decided that AllMS resident doctors including foreign national and sponsored candidates, fellows, and undergraduates would continue with their indefinite strike, including the suspension of academic activities, elective OPDs, ward, and OT services. However, emergency services, ICUs, emergency procedures, and emergency OT will remain operational.

The following resolutions were agreed upon:

- 1. Written assurance for the implementation of the Central Protection Act.
- CBI Inquiry: The general body welcomed the High Court's verdict and called for a fair and transparent investigation.
- Suspension of the former Principal pending inquiry, along with a public apology for offending the sentiments of the victim and the medical community.
- 4. Granting martyr status to the victim and naming a building/library at RG Kar MC&H hospital in her honor.
- 5. Providing adequate compensation to the doctor's family.
- Condemnation of the police assault on the protesting resident doctors and a call for strict action against the officers involved.

The general body emphasized that the implementation of the Central Protection Act is urgently needed. Despite the Act's introduction, no decisive action has been taken to address the ongoing attacks on doctors.

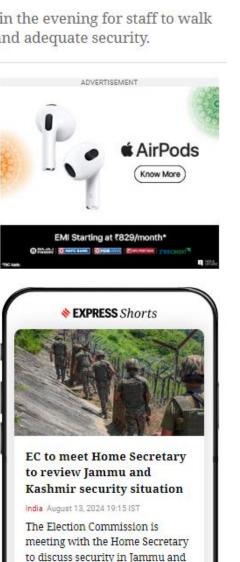
Page 1/2

After Kolkata doctor's rape-murder, NMC asks medical colleges to ensure safe workplace, send report within 48 hrs of each incident

The NMC notice goes on to say that all corridors and campus be well lit in the evening for staff to walk safely from one place to the other, other than installing CCTV cameras and adequate security.



working environment. Measures such as installing CCTV cameras in sensitive areas and availability of adequate security staff have been suggested.





RG Kar Medical College and Hospital rape-murder incident: The CBI has taken over the Kolkata rape and murder case and is sending a specialised medical and forensic team from Delhi to Kolkata. The team is scheduled to depart early tomorrow morning.

8:35 PM · Aug 13, 2024 · 23.4K Views

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की जांच अपने <mark>हाथ में ले ली</mark>। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एजेंसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं, जिसमें राज्य पुलिस को मामले के दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ दिल्ली से सीबीआई अधिकारियों का एक दल बुधवार को कोलकाता पहुंचेगा।





Three daily rape cases in India; Delhi, UP most unsafe for women: NCRB data



Aryata Nandi

m December 13, 2023

Modified : December 13, 2023

MUST READ

Hate speech against Muslims: BJP MLAs T Raja Singh, Nitesh Rane booked in Maharashtra

JANUARY 9, 2024

Hundreds missing from Gaza's Al-Aqsa Hospital, only 5 doctors remain: WHO

JANUARY 9, 2024

"Today is truly the New Year for me...": Full text of Bilkis Bano's statement

JANUARY 8, 2024

"Only Ayodhya, Lakshadweep...": EaseMyTrip suspends all Maldives flight bookings amid row over anti-PM Modi posts

JANUARY 8, 2024





Protest in Support and Solidarity with

> 20 Year Struggle

India lodged average 86 rapes daily, 49 offences against women per hour in 2021: **NCRB** data

Among states, Rajasthan (6,337) was on top of the list followed by Madhya Pradesh (2,947), Maharashtra (2,496) and Uttar Pradesh (2,845), while Delhi recorded 1,250 rape cases in 2021.

August 31, 2022 03:40 pm | Updated 06:03 pm IST - New Delhi

PTI



Immediately Revoke the Illegal

Release of the 11 Convicted of

Gang- Rape and ATTEGOR.

Nearly 77 Rape Cases Reported In India On Average In 2020: Report

Overall, 3,71,503 cases of crime against women were reported across the country last year, down from 4,05,326 in 2019 and 3,78,236 in 2018, the NCRB, which functions under the Union home ministry, stated.

India News | Press Trust of India | Updated: September 15, 2021 6:32 pm IST

TRENDING

NOTV

Bengaluru CEO Kills Her 4-Year-Old Son In Goa, Caught With Body In Bag

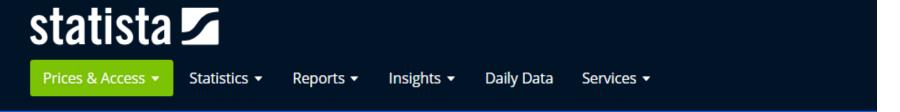
VITTV

"Sack President, Summon Minister": Maldives Opposition Defends PM Modi

WITW

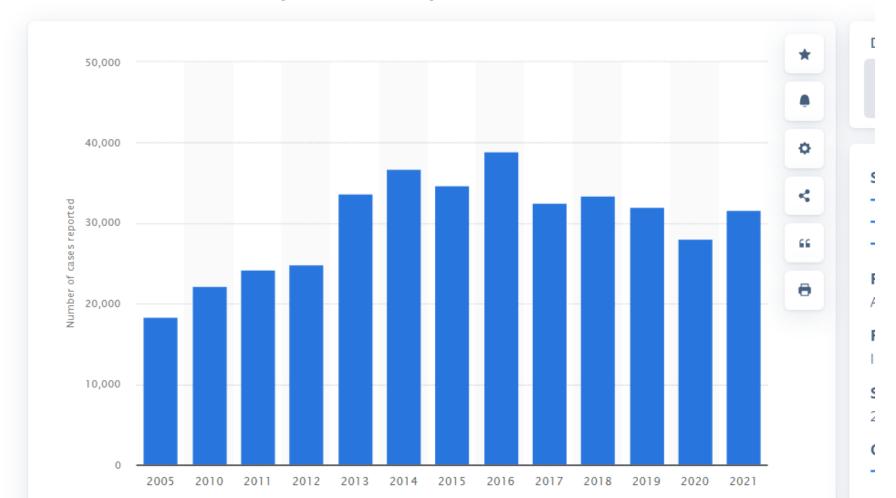
Jeffrey Epstein Filmed "Sex Tapes" Of Bill Clinton, Prince Andrew: Report





Society > Crime & Law Enforcement

Total number of rape cases reported in India from 2005 to 2021

















UPPSC,RO/ARP,BPSC,UP TEST SERIES

TEST SERIES)

35+ MOCK TESTS

- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

UPP

TEST SERIES)

- 20+ MOCK TESTS
- 8+ PYQ'S
- 25+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

Download | Application **Apni Pathshala**

7878158882

🕟 Apni.Pathshala 🧧 Avasthiankit

🕇 AnkitAvasthiSir 💟 kaankit

ANKIT AVASTHI SIR







A

GA FOUNDATION



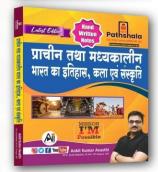


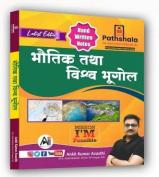


6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट













अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

- → सिन्धु नदी का उद्यम क्षेताका प्रवितिय क्षेत्र में बीखर पू → तिल्बत में इस निर्ण को सिंगी खंबान कहते हैं।
- → यह पमचीक नामक स्थान की भारत में प्रवेश करती है। - घट नदी भारत में लहान तथा जास्कर श्रीनी के बीच
- वहती है।
- -) पाकिस्तान में यह सरक (Attock) नामक स्थानों पर मैवानों में प्रवेश करती है।
- → पाकिस्तान में कराँची के पास डेस्टा बनाते हुए धर अस्व सागर में जिस्ती है।
- → सिंह्य नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक निदेवों :-रयोज , तुषा , दुनजा , गिलागीट , स्वात , काबुल तथा गीगल
- -) इसकी अनुय बायें हाथ की सहायक निदयां क्रीसम , चिनाव रावी , व्यास , सत्तवं , ट्रांस तथा जारकर
- → सिंघु भी पंचनद भान में निठानकीट नामक स्थान पर मिलती 🖺
- → 'लैंह' मिंधुं नदी के किनारें स्थित है।

4444

ं दीलम :- इस नवी का उत्गम जम्मू कवमीर में



Title:

Date: __/__/_

वैरिनाग झील से होता है।

- * यह नदी वूलर सील का निर्माण करती है भी भारत की सबसे बड़ी मीढ़े पानी की सील है।
- -) इस निक के किनारे भीनगर स्थित है।
- -) किश्वानगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी हैं।
- ्र इस नदी पर तुलकुल परियोजना प्रस्तावित है। थए एक नीवहन परियोजना दे।
- → यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तरिहरीय सीमा का निमिं करती है।
- ii) चिनाब : चिनाब नदी का उपगम हिमाचल प्रदेश में वारालन्द्या दर्व के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
- 🛶 उ ६ ८ में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन प्रीयीजनाएँ स्थित है।

उदाहरण :- दुलहस्ती , सतान , बगितहार

- 🛶 यह सिंधु नदी की सबसे वडी शद्ययं नदी 🗞।
- iii) <u>रावी</u>: = वावी नदी का उद्गम शैहताँग दर्रे के पास भी हिमान्यल उदेश में हीता है।
- → हिमायस प्रवेश में इन नदी पर प्रमेश बाँद्य स्थित है।
- → पंजाब में इस नदी पर धीन परियीजना स्थित E।

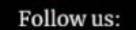


CALL HOW MAY I HELP YOU CENTRE

787815882







AnkitInspiresIndia

















The Economic Times

https://m.economictimes.com > etsundaymailer

Why have European car makers struggled to succeed in ...



Team-BHP

https://www.team-bhp.com > News :

Automobile companies in India: Why are they struggling



Chicago Tribune

https://www.chicagotribune.com > 2021/02/19 > top-au...

Top automakers have struggled to succeed in India — can Ford ...





Quora

https://www.quora.com > Why-EU-car-makers-failing-i...





Why have European car makers struggled to succeed in India?

By Lijee Philip, ET Bureau - Last Updated: Aug 10, 2024, 11:36:00 PM IST



Synopsis

European brands have failed to capitalise on successive waves of boom in the Indian car market. With Chinese brands pushing them out and the western market stagnating, India remains the great hope. ET looks at what they can do



European car makers in India, who won hearts, have yet to make any significant impact in one of the fastest growing passenger vehicle markets in the world.

Remember Opel Astra? It was India's first tryst with German technology on the roads. With automatic transmission — a rarity in those days — ventilated disc brakes and a CFC-free air-conditioning system, Astra quickly became the car to dream for. It single-handedly launched the premium luxury sedan segment in India. Opel, then owned by Detroit, US-based auto major General Motors, doubled down,



यूरोपियन कार निर्माता अपने उन्नत तकनीकी ज्ञान और प्रीमियम ब्रांड छिव के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। फिर भी, भारत के तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल बाजार में, इन ब्रांडों को उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिल पाई है। 2024 तक यूरोपीय कार निर्माताओं को भारतीय बाजार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई का संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक, और बाजार की जटिलताओं से है।

भारत में यूरोपीय कार कंपनियों का खराब प्रदर्शन लंबे समय से जारी है। चाहे वह रेनॉ-निसान (Renault-Nissan) का गठबंधन हो, प्यूज़ो और सिट्रोएन की साझेदारी, या स्कोडा-फॉक्सवैगन (Skoda-Volkswagen) का गठजोड़ ये सभी एशियाई कार कंपनियों के मुकाबले काफी पीछे हैं। इसके विपरीत, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), हुंडई (Hyundai), किआ (Kia), और भारतीय ऑटो कंपनियाँ जैसे टाटा मोटर्स (Tata Motors) और महिंद्रा (Mahindra) ने बेहतरीन प्रदर्शन (excellent performance) किया है।











European Car Brands



























































Share of Cars in India by Country of Origin

Country of Origin	2019	2020	2021	2022	2023	H1'24
Japan	61.6%	57.4%	53.3%	49.3%	49.8%	50.4%
India	13.1%	12.9%	17.5%	22.7%	24.0%	25.2%
Korea	19.5%	23.7%	22.6%	21.3%	20.9%	20.2%
Europe	4.8%	4.5%	4.8%	5.0%	3.7%	2.8%
Others	0.9%	1.4%	1.7%	1.6%	1.6%	1.4%

Source: Jato Dynamics

बाजार में बदलाव (MARKET IN TRANSITION)

भारत एक ऐसा बाजार है जो तेजी से बदल रहा है, जबिक यूरोप स्थिरता और पिरपक्वता के करीब पहुंच रहा है। भारत में एक बड़ी जनसंख्या है जो जल्द ही दोपहिया वाहनों से चारपिहया वाहनों की ओर बढ़ने वाली है, लेकिन पिश्चमी कार ब्रांड यह समझने में असफल रहे हैं कि भारत और यूरोप के पहले-बार के खरीदारों की आवश्यकताएँ बहुत अलग हैं।

यूरोपीय कार निर्माता बताते हैं कि भारत और यूरोप के बीच के नियामक नियमों (regulatory norms) में बड़े अंतर हैं, जो भारत के लिए लंबी अविध की रणनीति बनाना कठिन बनाते हैं। इसके अलावा, हर बाजार की विशेषताएँ, प्रतिस्पर्धा के मानक, विभिन्न सेगमेंट में मांग का फैलाव, लागत की प्राथमिकताएँ, और तकनीकी विकास का स्तर भी उत्पादन प्रक्रिया और सामग्री के चयन को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि यूरोपीय ब्रांडों को भारत में सफलता पाने में कठिनाई हो रही है।

<mark>यूरोपीय कार कंपनियों की रणनीतिक चूक:</mark> यूरोपीय कार कंपनियों की गलत उत्पाद रणनीतियों के कारण उनके पोर्टफोलियो में सीमित विकल्प रह गए हैं। वे उच्च लाभ वाले बाजारों जैसे यूरोप और चीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे भारत जैसे बाजारों में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

भारतीय ग्राहकों की प्राथमिकता: एक पूर्व भारतीय सीईओ का कहना है, "भारतीय ग्राहक मूल्य-संवेदनशील होते हैं, बजट से सीमित नहीं। उन्हें उन 'फायदों' के लिए ज्यादा क्यों देना चाहिए जो उनकी जरूरतों के मुताबिक नहीं हैं?" रवी भाटिया, निदेशक, जाटो डायनेमिक्स, कहते हैं, "यूरोपीय उत्पादों की इंजीनियरिंग और डिजाइन अक्सर भारतीय ग्राहकों की प्राथमिकताओं और नियमों से मेल नहीं खाती।"

<mark>सुरक्षा में अवसर गंवाया:</mark> भारत में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामले और बेहतर सड़कों के कारण सुरक्षा फीचर्स को लेकर ग्राहकों की सोच में बदलाव आया है। हालांकि, यूरोपीय कंपनियां इस मौके को भुनाने में असफल रहीं, जबकि टाटा मोटर्स ने इसे अपनी ब्रांड पुनर्जीवन रणनीति में शामिल कर लिया।

किफायती उत्पादन में मुश्किल: सुधीर राव, जो जीएम, रेनॉल्ट और स्कोडा के भारतीय शाखाओं का नेतृत्व कर चुके हैं, का कहना है कि यूरोपीय निर्माताओं के लिए भारतीय बाजार में परिष्कृत कारों को स्थानीयकृत करना और लाभ कमाना कठिन है। दूसरी ओर, जापानी और कोरियाई कंपनियों ने ईंधन की बचत, कम रखरखाव लागत, और किफायती दामों को प्राथमिकता देकर बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की।

ये गलतियां करते हैं यूरोपियन ब्रांड्स, जिससे उनकी कारों को भारत में पसंद नहीं किया जाता है:

- 1. उच्च कीमतें (High Prices): यूरोपीय ब्रांड्स की कारें भारतीय बाजार में आमतौर पर महंगी होती हैं, जो अधिकांश भारतीय उपभोक्ताओं के बजट से बाहर होती हैं। भारतीय ग्राहक वैल्यू फॉर मनी (value for money) पर अधिक ध्यान देते हैं, जो कि इन ब्रांड्स की कारों में कम होता है।
- 2. ईंधन दक्षता में कमी (Lack of Fuel Efficiency): भारतीय बाजार में कारों की ईंधन दक्षता (fuel efficiency) एक महत्वपूर्ण कारक है। यूरोपीय कारें, हालांकि उन्नत तकनीक से लैस होती हैं, लेकिन उनकी ईंधन दक्षता एशियाई कारों की तुलना में कम होती है, जिससे वे भारतीय ग्राहकों के लिए आकर्षक नहीं बन पातीं।
- 3. कम सर्विसिंग नेटवर्क (Limited Servicing Network): यूरोपीय ब्रांड्स का सर्विसिंग और सपोर्ट नेटवर्क भारत में पर्याप्त नहीं है। इससे ग्राहकों को सर्विसिंग और मेंटेनेंस में कठिनाई होती है, जो कि उनकी कारों की लोकप्रियता को कम कर देती है।

The prices of luxury cars will be reduced by 38% after the free trade agreement



Current price	Likely post-FTA
₹84 lakh	₹52 lakh
₹89 lakh	₹55 lakh
₹48.6 lakh	₹30 lakh
₹21 lakh	₹13 lakh
₹76.4 lakh	₹47.4 lakh
₹2.5 crore	₹1.5 crore
₹2.5 crore	₹1.5 crore
	₹84 lakh ₹89 lakh ₹48.6 lakh ₹21 lakh ₹76.4 lakh ₹2.5 crore



5 Star Safety | 14-18 kmpl | 177-189 bhp

Rs. 43.90 Lakh onwards

Avg. Ex-Showroom price

Get Best Offer



★ 4.6/5 | 55 Ratings



5 Star Safety | 13 kmpl | 369 bhp

Rs. 72.90 Lakh onwards

Avg. Ex-Showroom price

Get Best Offer

★ 4.5/5 | 64 Ratings



BMW X1 >

5 Star Safety | 16-20 kmpl | 134-148 bhp

Rs. 49.50 Lakh onwards

Avg. Ex-Showroom price

Get Best Offer





Renault KWID

Rs. 4.69 Lakh

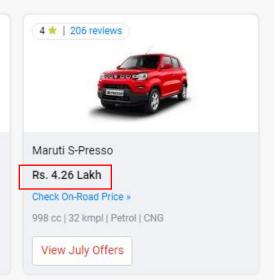
Check On-Road Price »

999 cc | 22 kmpl | Petrol

View July Offers



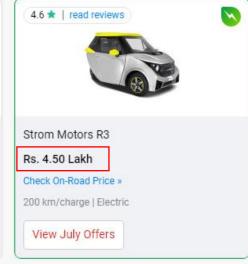


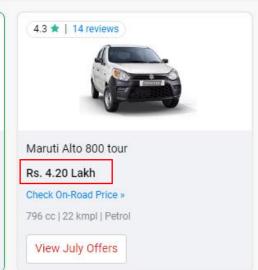


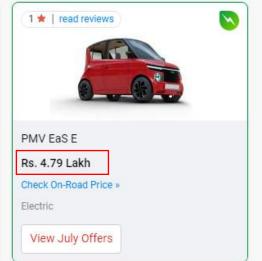


Hatchback









- 4. भारत के लिए अनुकूलन में कमी (Lack of Localization): यूरोपीय कार मैन्युफैक्चरर्स भारतीय बाजार की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने में असफल रहे हैं। उनकी कारें भारतीय सड़कों और जलवायु के अनुकूल नहीं होतीं, जिससे भारतीय उपभोक्ता उन्हें अपनाने से हिचकिचाते हैं।
- 5. उपभोक्ता प्राथमिकताओं की समझ की कमी (Lack of Understanding of Consumer Preferences): यूरोपीय ब्रांड्स भारतीय ग्राहकों की प्राथमिकताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। यहां के ग्राहक कॉम्पैक्ट, सस्ती, और कम मेंटेनेंस वाली कारों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि यूरोपीय कारें अक्सर बड़े आकार और लग्ज़री सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- 6. उच्च आयात शुल्क: भारतीय सरकार द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क यूरोपीय कारों की कीमत को काफी बढ़ा देते हैं। इससे कारें महंगी हो जाती हैं, जो उन्हें भारतीय ग्राहकों के लिए कम आकर्षक बनाता है।

हुई है।

- 6. कम मार्केटिंग (Less Aggressive Marketing): भारतीय बाजार में ब्रांड की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आक्रामक मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। यूरोपीय ब्रांड्स ने इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किया, जिससे उनकी ब्रांड जागरूकता और बिक्री प्रभावित
- 7. लंबी अवधि की निवेश योजनाओं की कमी (Lack of Long-term Investment Plans): यूरोपीय कार मैन्युफैक्चरर्स ने भारत में दीर्घकालिक निवेश योजनाओं पर जोर नहीं दिया, जैसे कि स्थानीय उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करना। इससे उनकी लागत अधिक होती है, और वे प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाते।
- 8. सरकार के साथ कमजोर समन्वय (Weak Coordination with Government Policies): यूरोपीय ब्रांड्स ने भारतीय सरकार की नीतियों और नियमों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने में देरी की, जिससे वे भारतीय बाजार में सफल नहीं हो सके।

बिक्री और टिकाऊपन पर फोकस:

अगर कोई ऑटो कंपनी शुरुआत में मजबूत ऑफ्टर-सेल इकोसिस्टम तैयार नहीं करती, तो वह असफल हो जाती है। यूरोपीय ब्रांड्स टिकाऊ लेकिन महंगी कारों पर फोकस करते हैं, जो भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल नहीं होतीं। इसके विपरीत, एशियन कंपनियां सस्ते और किफायती मॉडल्स के साथ आती हैं, जो भारतीय ग्राहकों को अधिक आकर्षित करती हैं।







Top 10 **Bestselling Cars in India** in **June 2024**

Car Model	Units Sold		
1. Tata Punch	18,238 units	1	2
2. Maruti Suzuki Swift	16,422 units		
3. Hyundai Creta	16,293 units	3	4
4. Maruti Suzuki Ertiga	15,902 units	-0-0	E . 8
5. Maruti Suzuki Baleno	14,895 units	5	6
6. Maruti Suzuki WagonR	13,790 units		
7. Maruti Suzuki Dzire	13,421 units	7	8
8. Maruti Suzuki Brezza	13,172 units		
9. Mahindra Scorpio	12,307 units		
10. Tata Nexon	12,066 units	9	10
			6





India is the world's 4th largest vehicle market.

But why are luxury cars so expensive here?



Few reasons

- High Taxes
- Low volumes
- High dealer margins
- Transportation costs
- High Manufacturer margins. Most manufacturers in US/Europe have low single-digit margins and in India, it is at least in double digits.





"So, first you pay **import duties (100%)** then you pay **GST (48-50%)** and then you have a **registration tax of 15%.** So it's duties on duties on duties, a **multiple layer of duties** which is keeping this sector very niche."

~ Former head of Audi India, Balbir Singh Dhillon





The cost of super luxury cars like Lamborghini & Ferrari goes up by nearly three times when sold in India due to the taxes & duties.

If you plan to buy a Lamborghini today, you'll have to spend over 150% on duties & taxes combined.











All Images News Shopping Videos Books Maps : More Tools

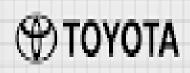




What is the import duty on cars in India? Cars with CIF (Cost, Insurance, and Freight) value over USD 40,000 incur a 100% customs tax, while those under USD 40,000 face a 60% import duty. Used vehicle import tax stands at 125%. 30 Apr 2024



The Best Asian Car Brands













PROTON



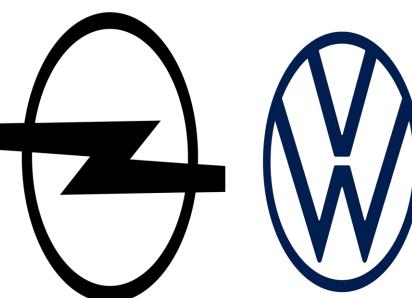
European Car Brands





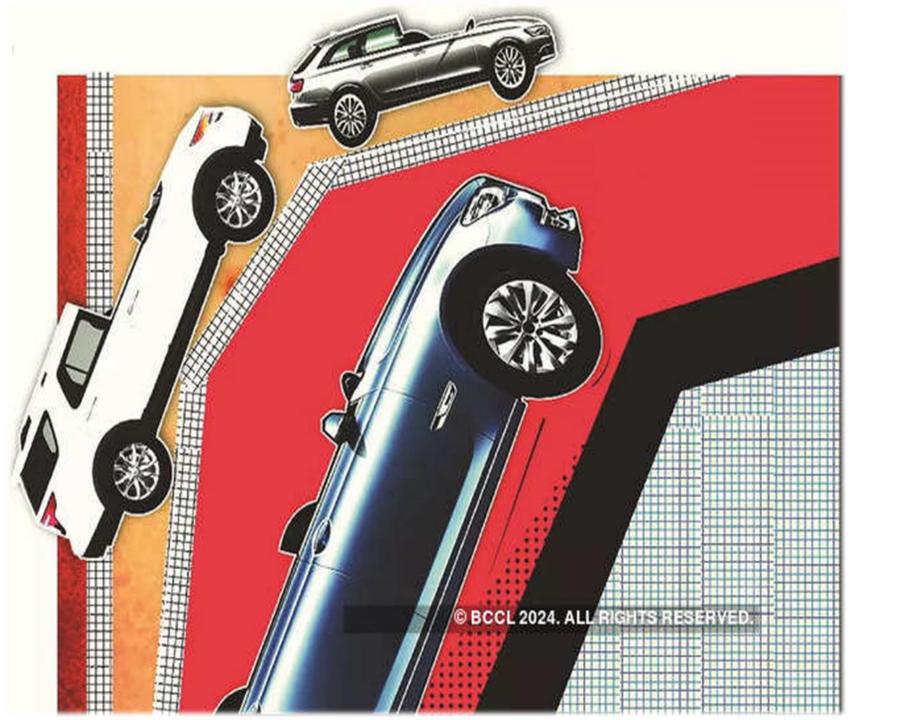












लग्जरी कारों में यूरोप का दबदबा:

लग्जरी कार सेगमेंट में यूरोपीय ब्रांड्स, जैसे मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू, और ऑडी, का वर्चस्व है। यूरोप को ग्लोबल लक्जरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, जो भारतीय ग्राहकों के मन में विश्वास पैदा करता है। साथ ही, भारतीय लग्जरी कार खरीदार ग्लोबल स्टैंडर्ड और टेस्ट को प्राथमिकता देते हैं, जिससे यूरोपीय ब्रांड्स उनकी पहली पसंद बनते हैं। इन ब्रांड्स की उच्च गुणवत्ता, प्रीमियम डिजाइन, और अत्याधुनिक तकनीक भी इन्हें लग्जरी कार बाजार में अग्रणी बनाती है।



कारों की विश्वसनीयता पर सवाल:

- 1.ड्राइविंग अनुभव शानदार, लेकिन विश्वसनीयता पर सवाल: यूरोपीय कारें ड्राइविंग और हैंडलिंग के मामले में शानदार होती हैं, लेकिन जब विश्वसनीयता की बात आती है, तो लोग इन्हें लेने से कतराते हैं। VAG ग्रुप का उदाहरण: VAG ग्रुप एक बड़ा और धनी समूह है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। आम धारणा यही है कि ये कारें विश्वसनीय नहीं हैं।
- 2. अन्य यूरोपीय ब्रांड्स: सिर्फ VAG ग्रुप ही नहीं, बल्कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ट, JLR और फोर्ड भी (भले ही फोर्ड एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन यूरोप और विकासशील देशों में इसके अधिकांश काम यूके में होते हैं) अक्सर विश्वसनीय नहीं माने जाते।
- 3. एशियाई ब्रांड्स की विश्वसनीयता: दूसरी ओर, टोयोटा, होंडा, सुज़ुकी, निसान (हालांकि कुछ मॉडलों की विश्वसनीयता खराब है) और यहां तक कि ह्यूंदै जैसी कंपनियां हमेशा विश्वसनीय मानी जाती हैं

- 4. भारत ही नहीं, दुनिया भर में समस्या: यह मुद्दा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी देखा जाता है, जहां सड़कें अच्छी हैं और ड्राइविंग का तरीका भी सभ्य है।
- 5. सर्विस के बारे में कई शिकायतें: भारत में स्थिति और भी खराब हो जाती है, खासकर जब यूरोपीय ब्रांड्स की खराब सर्विस का अनुभव होता है (स्कोडा, वीडब्ल्यू, फिएट, ऑडी जैसी कंपनियों की सर्विस के बारे में कई शिकायतें हैं)। वारंटी का सम्मान न करना और नकली पुर्जों का इस्तेमाल करना भी इन कारों की विश्वसनीयता को और कम कर देता है।

भारत में यूरोपीय कार ब्रांड्स के सफल होने के तरीके:

मूल्य-प्रभावी मॉडल्स: भारतीय बाजार के लिए किफायती और प्रीमियम-लागत के मॉडल पेश करें।

स्थानीयकरण: कारों को भारतीय सड़कों और मौसम के अनुरूप डिजाइन करें।

मजबूत सर्विस नेटवर्क: बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस और व्यापक सर्विस नेटवर्क स्थापित करें।

विश्वसनीयता बढ़ाएँ: कारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करें।

ग्राहक की जरूरतों पर फोकस: भारतीय ग्राहकों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को समझें और उन पर ध्यान दें। रेनॉल्ट इंडिया के सीईओ का भरोसा: खोई हुई स्थिति को फिर से हासिल करेंगे

रेनॉल्ट इंडिया के कंट्री सीईओ और एमडी वेंकटराम मिमलापल्ले कहते हैं। कि रेनॉल्ट उन पहले यूरोपीय निर्माताओं में से एक था जिसने भारत के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मॉडल पेश किए

रेनॉल्ट के पास वर्तमान में भारतीय बाजार का थोड़ा सा हिस्सा, लगभग 1% है, जो पहले 4% तक पहुंच गया था। रेनॉल्ट ने डस्टर से शुरू होकर क्विड तक कई बड़े लॉन्च किए, लेकिन वे अपनी गति खो बैठे। इसका कारण उनके वैश्विक संकट और ग्राहक संतुष्टि और डीलर संबंधों में स्थानीय कार्यान्वयन की कमजोरियाँ थीं।



Volkswagen और <mark>Škoda</mark> का वापसी का प्रयास:

Volkswagen और Škoda ने हाई-वॉल्यूम सब-4 मीटर सेगमेंट से बाहर निकलने के बाद अब नए मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। Škoda Auto Volkswagen India के एमडी और सीईओ, पीयूष अरोड़ा ने बताया कि उनकी कंपनी ने ग्राहकों की मांग को समझते हुए भारत के लिए एक नया कॉम्पैक्ट SUV मॉडल तैयार किया है, जो 2025 के पहले हिस्से में लॉन्च होगा। यह <mark>SUV</mark> सेगमेंट भारत के वाहन बाजार का 50% से अधिक हिस्सा बनाता है और इसमें सालाना 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। <u>Škoda</u> को उम्मीद है कि यह नया मॉडल 2026 तक भारत में 1 लाख वार्षिक बिक्री के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

Citroen का नया दांव:

Citroen ने भारत में अपना चौथा मॉडल, Basalt Coupe-SUV लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹7.99 लाख है। यह मॉडल टाटा की नई Curvy का प्रतिस्पर्धी है।





- T 44

अमेरिका और भारत में ऑडी Q7 की कीमत में अंतर:

<mark>आयात शुल्क:</mark> अमेरिका में ऑडी Q7 की कीमत 35 लाख रुपये है, लेकिन भारत में 125% आयात शुल्क के कारण यह 75 लाख रुपये हो जाती है।

अतिरिक्त लागत: शिपिंग, बीमा, और अन्य शुल्क जोड़ने पर कीमत और बढ़ जाती है।

<mark>ड्राइविंग साइड का अंतर:</mark> अमेरिका की कारें बाएं हाथ की ड्राइविंग के लिए होती हैं, जिन्हें भारत में चलाने के लिए दाएं हाथ की ड्राइविंग में बदलना पड़ता है।

कुल लागत: सभी खर्चों को जोड़ने पर कीमत 85 लाख रुपये तक पहुँच सकती है।

भारत के वाहन बाजार में भविष्य की बड़ी संभावनाएँ, चुनौतियों के बावजूद:

2019 में, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया, जहाँ लगभग 4 मिलियन वाहन बेचे गए। भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार, आने वाले वर्षों में इस बाजार में और वृद्धि की उम्मीद है, जो देश की युवा और बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के कारण होगी।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2027 तक इस बाजार की वार्षिक वृद्धि दर 11.3% रहने का अनुमान है। SUVs की बढ़ती लोकप्रियता, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में वाणिज्यिक वाहनों की मांग, और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग इस वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे।







UPPSC,RO/ARP,BPSC,UP TEST SERIES

TEST SERIES)

35+ MOCK TESTS

- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

UPP

TEST SERIES)

- 20+ MOCK TESTS
- 8+ PYQ'S
- 25+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

Download | Application **Apni Pathshala**

7878158882

🕟 Apni.Pathshala 🧧 Avasthiankit

🕇 AnkitAvasthiSir 💟 kaankit

ANKIT AVASTHI SIR







A

GA FOUNDATION



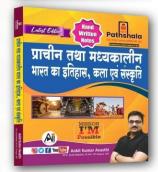


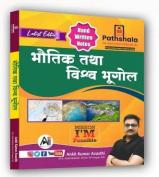


6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट













अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

- → सिन्धु नदी का उद्यम क्षेताका प्रवितिय क्षेत्र में बीखर पू → तिल्बत में इस निर्ण को सिंगी खंबान कहते हैं।
- → यह पमचीक नामक स्थान की भारत में प्रवेश करती है। - घट नदी भारत में लहान तथा जास्कर श्रीनी के बीच
- वहती है।
- -) पाकिस्तान में यह सरक (Attock) नामक स्थानों पर मैवानों में प्रवेश करती है।
- → पाकिस्तान में कराँची के पास डेस्टा बनाते हुए धर अस्व सागर में जिस्ती है।
- → सिंह्य नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक निदेवों :-रयोज , तुषा , दुनजा , गिलागीट , स्वात , काबुल तथा गीगल
- -) इसकी अनुय बायें हाथ की सहायक निदयां क्षेतम , चिनाव रावी , व्यास , सत्तवं , ट्रांस तथा जारकर
- → सिंघु भी पंचनद भान में निठानकीट नामक स्थान पर मिलती 🖺
- → 'लैंह' मिंधुं नदी के किनारें स्थित है।

4444

ं दीलम :- इस नवी का उत्गम जम्मू कवमीर में



Title:

Date: __/__/_

वैरिनाग झील से होता है।

- * यह नदी वूलर सील का निर्माण करती है भी भारत की सबसे बड़ी मीढ़े पानी की सील है।
- -) इस निक के किनारे भीनगर स्थित है।
- -) किश्वानगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी हैं।
- ्र इस नदी पर तुलकुल परियोजना प्रस्तावित है। थए एक नीवहन परियोजना दे।
- → यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तरिहरीय सीमा का निमिं करती है।
- ii) चिनाब : चिनाब नदी का उपगम हिमाचल प्रदेश में वारालन्द्या दर्वे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
- 🛶 उ ६ ८ में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन प्रीयीजनाएँ स्थित है।

उदाहरण :- दुलहस्ती , सतान , बगितहार

- 🛶 यह सिंधु नदी की सबसे वडी शद्ययं नदी 🗞।
- iii) <u>रावी</u>: = वावी नदी का उद्गम शैहताँग दर्रे के पास भी हिमान्यल उदेश में हीता है।
- → हिमायस प्रवेश में इन नदी पर प्रमेश बाँद्य स्थित है।
- → पंजाब में इस नदी पर धीन परियीजना स्थित E।

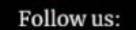


CALL HOW MAY I HELP YOU CENTRE

787815882







AnkitInspiresIndia







